राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

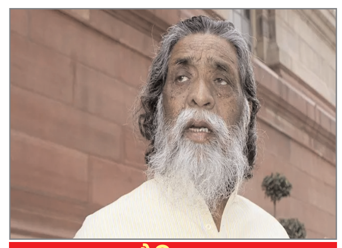

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापुर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, सोमवार , 15 दिसंबर 2025
वर्ष 14, अंक 242, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित

नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐहार में अव्यवस्था, घंटों बंद रहता है अस्पताल का गेट...03

खाकी बनाम खादी :-55 दिनों बाद टूटा सियासी सस्पेंस, भाजपा नेता प्रीतम सिंह किसान लखनऊ से गिरफ्तार ..04

केरल में आधी से अधिक आबादी हिंदू पर भी 75 सालों से भाजपा को क्यों है बड़ी जीत का इंतजार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

केरल में स्थानीय निकाय चुनावों में यूडीएफ को अच्छी जीत हासिल हुई है. अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन को सेमीफाइनल माना जा रहा था. इसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ फर्स्ट क्लास के साथ पास हुआ है. उसे राज्य के छह नगर निगमों में से चार और 87 नगरपालिकाओं में से 54 में जीत मिली है. इसी के साथ ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों में भी उसे शानदार जीत मिली है. तिरुवनंतपुरम निगम में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को जीत मिली है. लेकिन, यहां भी यूडीएफ ने अपनी सीटें बढ़ाई है. एलडीएफ को सबसे बड़ी हार तिरुवनंतपुरम में मिली है. यहां उसका 45 वर्षों का राज खत्म हुआ है।

कुल मिलाकर पहली बार भाजपा इस चुनाव में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करवाने में कामयाब हुई है. उसने पहली बार तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर कब्जा किया है. पार्टी ने तिरुवनंतपुरम निगम में 101 सीटों में से 50 सीटें जीतीं, जो बहुमत से एक कम है. इससे भाजपा को केरल में पहली बार महापौर पद मिलने की संभावना बन गई है. राज्य की महिला आईपीएस अधिकारी 64 वर्षीय सेवानिवृत्त डीजीपी आर श्रीलेखा को महापौर पद के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा है. श्रीलेखा ने शश्थमंगलम वार्ड से जीत हासिल की है।

भाजपा को क्यों नहीं मिलती बड़ी जीत?

लेकिन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के करीब 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार बनाने वाली भाजपा बीते 75 सालों में केरल में क्यों नहीं अपनी प्रभावी

उपस्थिति दर्ज करवाई. केरल की डेमोग्राफी की बात करें तो इस राज्य में करीब 54 फीसदी आबादी हिंदू हैं. दूसरे नंबर मुस्लिम हैं. यहां की आबादी में 26.6 फीसदी मुस्लिम और 18.4 फीसदी ईसाई समुदाय के लोग हैं. केरल देश का एक सबसे विकसित राज्य है. यहां साक्षरता की दर 96 फीसदी से अधिक है. अब सवाल है कि एक हिंदू बहुसंख्यक राज्य होने के बावजूद केरल में आज तक भाजपा कोई बड़ी जीत क्यों नहीं हासिल कर पाई।

लोकसभा में भाजपा को केवल सीट

जहां तक राज्य विधानसभा और लोकसभा की बात है तो यहां भी भाजपा पूरी तरह गायब है. 2021 के विधानसभा में यहां की 140 सीटों में से 99 पर एलडीएफ को जीत मिली थी. विपक्षी यूडीएफ को 41 सीटों पर जीत मिली थी. एलडीएफ के खाते में 45.43 फीसदी और यूडीएफ को 39.47 फीसदी वोट मिले थे. भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 12.41 फीसदी वोट मिले थे. इसी तरह 2024 के लोकसभा की बात करें तो यहां की 20 सीटों में से 18 पर यूडीएफ को जीत मिली थी. केवल एक सीट पर एलडीएफ और एक पर भाजपा को जीत मिली है. त्रिसूर लोकसभा सीटे से भाजपा के नेता सुरेश गोपी निर्वाचित हुए थे. जहां तक वोट प्रतिशत की बात है तो यूडीएफ को 45.21 फीसदी वोट मिले वहीं एलडीएफ को वोट प्रतिशत घटकर 33.60 फीसदी हो गया. दूसरी तरफ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का वोट प्रतिशत बढ़कर 19.24 फीसदी हो गया।

क्या लगातार मजबूत हो रही भाजपा

इस सवाल का जवाब हां है. बीते कुछ चुनावों के वोट प्रतिशत देखें तो पता चलता है कि राज्य में भाजपा मजबूत हो रही है. उसके वोट प्रतिशत बढ़ रहे हैं. लेकिन, वह अभी तक केरल में उस स्थिति में नहीं पहुंच पाई है कि वह निकट भविष्य में सरकार बनाने की योजना बना सके. दरअसल, केरल से उत्तर भाजपा के राज्यों जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार से काफी अलग है. यहां की आबादी अच्छी खासी शिक्षित है. यहां के सरकारी सिस्टम देश में संबवतः सबसे बेहतर स्थिति में. केरल का स्वास्थ्य सेक्टर यूरोपीय देशों को टक्कर देता है. दूसरी तरह केरल का इस्लाम भी उत्तर भारत से इस्लाम से अलग है. केरल में इस्लाम का आगमन व्यापार से रास्ते अरब से पहुंचा जबकि उत्तर भारत के इस्लाम में मुगलों का प्रभाव ज्यादा है. ऐसे में केरल के समाज में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के बीच ऐसा बंटवारा या विवाद नहीं दिखता है जितना कि उत्तर भारत में है. ऐसे में केरल का राष्ट्रवाद अलग किस्म का है. उसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी तरक्की है।

गले में रस्सी, चेहरे और मुंह पर चोट के निशान... उन्नाव में तीन दिन से लापता युवक का बगीचे में मिला शव

उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के अचलगंज थाना क्षेत्र स्थित बदरका गांव में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. गांव के बाहर एक बाग में मिले शव की पहचान 25 वर्षीय सुधीर पुत्र रामसजीव के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि सुधीर तीन दिन से लापता था, जिसकी शिकयात थाने में दर्ज कराई थी. गांव के लोगों ने रविवार सुबह बाग में शव देखा तो परिजनों और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि युवक के गले में रस्सी कसी हुई थी, जिससे प्रथम दृष्टया गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है. मृतक युवक सुधीर के चेहरे और मुंह पर चोट के निशान मिले हैं. माना जा रहा है कि हत्या से पहले उसके साथ मारपीट की गई. वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा।

गांव के बाहर बाग में मिला युवक का शव

जानकारी के मुताबिक, अचलगंज थाना पुलिस और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. मामले को गंभीरता से लेते हुए फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड टीम को मौके पर बुलाया गया. टीमों ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए और आसपास की जगहों की गहनता से जांच की. परिजनों ने बताया कि सुधीर का किसी से कोई विवाद नहीं था. वह तीन दिन पहले घर से निकला था और तब से लापता था।

पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया

फिलहाल, अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की तह तक जाने का प्रयास किया जा रहा है. जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. सीओ बीघापुर एमएन मिश्रा ने बताया की इस मामले में दो लोगों हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही है।

जब नेहरू की नैतिकता हुई तार-तार, लोकतंत्र का घोंटा गला, केरल की वो घटना जिससे अमेरिका से यूरोप तक मची थी खलबली

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

भारत प्राचीन काल से ही लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए विख्यात रहा है. वैशाली गणराज्य ने पहली बार दुनिया को लोकतंत्र से रूबरू कराया था. 1940 के दशक में कई देशों ने आजादी हासिल की थी, उनमें से भारत ऐसा राष्ट्र है, जहां लोकतंत्र आज भी फल-फूल रहा है. तमाम तरह की घटनाओं और आघात के बाद भी भारत का गणतंत्र आज भी हिमालय की तरह सिर उठाए अडिग और अविचल है. देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लोकतंत्र का अगुआ माना जाता है, पर उनकी सरकार पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को एकतरफा तरीके से बर्खास्?त करने का दाग भी है. उनके राजनीतिक करियर की उजली चादर पर यह ऐसा दाग है, जो इतिहास में दर्ज है और जिसको मिटाया नहीं जा सकता है. नेहरू सरकार ने संविधान के उस प्रावधान का इस्?तेमाल किया, जिसके बारे में देश के नीति-निर्माताओं ने शायद ही इस तरह से सोचा हो. पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 31 जुलाई 1959 को अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए केरल की पहली निर्वाचित सरकार को बर्खास्?त कर दिया था. बताया जाता है कि केरल की ईएमएस नंबूदरीपाद सरकार दुनियाभर में पहली कम्यूनिस्ट सरकार थी, जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए सत्ता हासिल की थी।

भारत में किसी चुनी हुई सरकार को पहली बार संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए सत्ता से बेदखल किया गया था. नेहरू सरकार ने आरोप केरल की नंबूदरीपाद सरकार पर राज्य की शासन व्यवस्था को उचित तरीके से न संभालने का आरोप लगाया गया था. केरल की लोकतांत्रिक सरकार को जब बर्खास्त किया गया था तो उस वक्त प्रदेश में मुक्ति संग्राम (विमोचन समरम - Vimochana

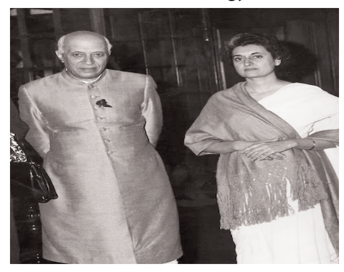

Samaram) चल रहा था. विरोध-प्रदर्शन के साथ ही हिंसक घटनाएं भी हो रही थीं. हालांकि, वामपंथी नेताओं का कहना था कि प्रदेश में जानबूझकर ऐसी घटना क्रिएट की गई थी. अमेरिकी और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों (CIA और MI5) के इसमें शामिल होने के भी आरोप लगे थे. कुछ हलकों में तो यह भी कहा जाता है कि केरल के 'चीन बनने' के खतरे से अमेरिका से यूरोप तक में खलबली मची हुई थी. वामपंथी सरकार का इस तरह से चुनकर सत्ता में आना उस वक?त न तो अमेरिका और न ही ब्रिटेन को सुहा रहा था. कहा जाता है कि इसी वजह से केरल की चुनी हुई वाम सरकार को गिराने की कथित तौर पर साजिश रची गई थी।

कैसे बर्खास्त हुई थी देश की पहली लोकतांत्रिक सरकार?

31 जुलाई 1959 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए केरल के निर्वाचित मुख्यमंत्री नंबूदरीपाद और उनकी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया. राज्य विधानसभा को भंग करने का आदेश दे दिया गया. यह फैसला कई महीनों से चल रहे विरोध-प्रदर्शनों और हिंसा के बाद लिया गया था. इससे एक ऐसी मिसाल कायम हुई, जिसमें गैर-कांग्रेस सरकारों के खिलाफ इस प्रावधान का इस्तेमाल आगे के दशकों में बार-बार किया गया. प्रधानमंत्री नेहरू ने शुरू में इस कदम को लेकर हिचक दिखाई थी (जैसा कि ब्रिटिश रिकॉर्ड से पता चलता है) लेकिन अंत में उन्होंने अपनी कैबिनेट की सलाह मानते हुए नंबूदरीपाद सरकार को हटाने पर सहमति दे दी. सरकार को हटाने का कारण कानून-व्यवस्था के बिगड़ने को बताया गया. हालांकि, आलोचकों का कहना था कि हिंसा जानबूझकर कराई गई थी, ताकि संवैधानिक हस्तक्षेप का बहाना बनाया जा सके।

अनुच्छेद 356 क्या है?

यह प्रावधान राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि अगर किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन न चल सके, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।

अनुच्छेद-356 का इस्तेमाल

केरल की कम्युनिस्ट सरकार को हटाए जाने से वह मिसाल बनी जिसे बाद में 'केरल मिसाल' कहा गया. इसका मतलब था राजनीतिक और वैचारिक विरोध के आधार पर चुनी हुई राज्य सरकार को हटाने के लिए अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल. इससे पहले यह अनुच्छेद पंजाब (1951) और पेप्सू (1953) में इस्तेमाल हो चुका था, लेकिन केरल का मामला पहली बार किसी कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ इसके प्रयोग का था. इसी से आगे चलकर इस संवैधानिक प्रावधान के राजनीतिक दुरुपयोग का रास्ता खुला. बाद के वर्षों में केंद्र में सत्ता में बैठी पार्टी को जो राज्य सरकारें असुविधाजनक लगीं, उनके खिलाफ अनुच्छेद 356 का बार-बार उपयोग किया गया, जिससे संविधान निर्माताओं द्वारा सोचे गए संघीय संतुलन (Federal Balance) पर गहरा असर पड़ा।

संक्षिप्त ख़बरें

कोहरे की चादर में कैद प्रयागराज, सुबह होते ही थम गई रफ्तार

धूप हुई बेअसर, गलन ने बढ़ाई ठंड।

प्रयागराज। शनिवार की सुबह जैसे ही शहर जागा, हर ओर धुंधली परछाइयों का सन्नाटा पसरा था। इस सीजन का अब तक का सबसे घना कोहरा शहर पर इस तरह छाया कि सड़कें पहचान में नहीं आ रही थीं। चौराहों की रफ्तार थम गई, वाहन रेंगते नजर आए और आम दिनों की चहल-पहल मानो कहीं गुम हो गई। दृश्यता बेहद कम होने के कारण लोग जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकले, बाकी शहर कोहरे की आगोश में सुस्त पड़ा रहा। बीते दो दिनों से मौसम मानो रोज़ नया रूप धर रहा है। शाम ढलते ही हल्की धुंध शहर की गलियों में उतर आती है, जो रात गहराने के साथ घने कोहरे में तब्दील हो जाती है। पूरी रात यह कोहरा अपनी पकड़ बनाए रखता है और सुबह तक शहर को जकड़े रहता है। सूरज उगने के बाद भी देर तक आसमान दूधिया परत में छिपा रहता है।कोहरे का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा। दिन में धूप की तीव्रता भी कमजोर पड़ गई है। सूरज निकलता तो है, लेकिन उसकी गर्माहट ठंड से लड़ने में नाकाम साबित हो रही है। तापमान में गिरावट के साथ ठिठुरन और गलन ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है। सुबह और शाम ठंड का प्रकोप सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है।लगातार बदलते मौसम ने लोगों को गर्म कपड़ों में लपेट दिया है। गली-मोहल्लों में अलाव जल उठे हैं, जिनके आसपास बैठकर लोग ठंड से राहत तलाशते नजर आ रहे हैं। प्रयागराज की यह सुबह सिर्फ कोहरे की नहीं, बल्कि उस ठंड की कहानी है, जिसने शहर की रफ्तार को थाम लिया और लोगों को सर्द एहसासों में समेट लिया।

यूनुस पर चौतरफा संकट, देश में बवाल, सूडान में छह बांग्लादेशी सैनिकों की मौत, दक्षिण अफ्रीका से भी आई बुरी खबर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ढाका- बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस चौतरफा संकट में घिरे हैं. बांग्लादेश में चुनाव आयोग के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया. वहीं अब अफ्रीका से दो बेहद चिंताजनक खबरें सामने आई हैं. एक तरफ सूडान में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन पर आतंकी हमले में बांग्लादेशी सैनिकों की जान गई है, तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका में अवैध तरीके से पहुंचे बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर देश से बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है. इन दोनों घटनाओं ने एक साथ बांग्लादेश की सरकार और सुरक्षा तंत्र की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सूडान के अशांत अबेई (Abyei) इलाके में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन NISFA पर हुए आतंकी हमले में बांग्लादेश के छह सैनिकों की मौत हो गई, बल्कि छह घायल हो गए।

हमले के बाद अब कैसे हैं हालात?

संयुक्त राष्ट्र के कैंप पर यह हमला एक ड्रोन के जरिए किया गया था. बांग्लादेश सेना के मुताबिक यह हमला इतना भीषण था कि इलाके में अब भी हालात पूरी तरह काबू में नहीं आए हैं और आतंकियों के साथ झड़प जारी है. सेना ने बताया कि घायल जवानों को निकालने और इलाज के लिए हरसंभव कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन क्षेत्र में न तो मजबूत प्रशासन है, न पुलिस व्यवस्था और न ही कोई प्रभावी न्यायिक ढांचा. संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, यह हमला पिछले तीन सालों में अबेई क्षेत्र में हुआ सबसे घातक हमला है, जिसमें अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।

बांग्लादेश के कितने सैनिक ह में शामिल?

स्थानीय प्रशासन का आरोप है कि विद्रोही गुटों ने हथियारबंद युवाओं के साथ मिलकर सुनियोजित और बर्बर हमले किए. बांग्लादेश लंबे समय से यूएन पीसकीपिंग मिशनों में बड़ा योगदान देने वाला देश रहा है और इस वक्त भी अफ्रीका के कई संघर्षग्रस्त इलाकों में उसके 6,000 से ज्यादा सैनिक और सुरक्षाकर्मी तैनात हैं. ऐसे में सैनिकों की मौत ने सरकार के सामने सुरक्षा, विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय दबाव से जुड़े कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मोहम्मद यूनुस ने भी इस हमले पर अफसोस जताया है।

बांग्लादेश के लिए दूसरी बुरी खबर क्या है?

इसी बीच साउथ अफ्रीका से आई दूसरी खबर ने बांग्लादेश की चिंता और बढ़ा दी है. जोहान्सबर्ग के ओआर टैम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 16 बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी वीजा के साथ पकड़ा गया है. ये सभी इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट से पहुंचे थे और जांच में सामने आया कि वे मानव तस्करी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं. साउथ अफ्रीका की बॉर्डर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि ये लोग संदिग्ध तरीके से स्थानीय यात्रियों के बीच घुलने-मिलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें अलग कर जांच की गई।

16 बांग्लादेशियों को किया जाएगा डिपोर्ट

अधिकारियों के अनुसार, इनके पास मौजूद दस्तावेज पूरी तरह फर्जी थे और यात्रा का उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं था. अब सभी 16 बांग्लादेशी नागरिकों को देश से डिपोर्ट किया जाएगा. इसके साथ ही जिस एयरलाइन ने इन्हें यात्रा की अनुमति दी, उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा और डिपोर्टेशन का खर्च भी उसी से वसूला जाएगा. साउथ अफ्रीका लंबे समय से बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों के नागरिकों की अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्रवेश को लेकर चिंता जताता रहा है।

धान खरीद प्रक्रिया में भेदभाव किए जाने के आरोप

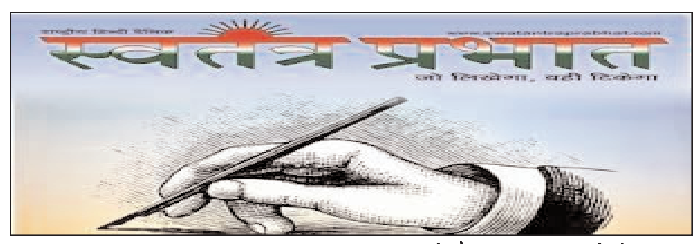

धान खरीद की सुस्त रफ्तार को लेकर किसानों में नाराजगी का माहौल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखीमपुर खीरी। जनपद में धान खरीद प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। सहकारिता विभाग के क्रय केंद्रों पर धान खरीद की गति बेहद धीमी, जबकि मार्केटिंग विभाग के केंद्रों पर धान खरीद तेजी से जारी है।सूत्रों के मुताबिक, अधिकतर लाटे मार्केटिंग केंद्रों को अलॉट किए जा रहे हैं, जिससे सहकारिता विभाग के 99 केंद्र धीमी रफ्तार से धान खरीद कर पा रहे हैं। चावल न उतरने के कारण सहकारिता केंद्रों पर खरीद ठप जैसी स्थिति बनी हुई है।डिप्टी आरएमओ की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि भेदभावपूर्ण तरीके से अपने पसंदीदा क्रय केंद्रों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, क्रय नीति के खिलाफ मार्केटिंग विभाग में एक प्रभारी को दो-दो केंद्रों की जिम्मेदारी दी गई है।सूत्रों का दावा है कि मिलर्स पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वे पहले मार्केटिंग केंद्रों का ही चावल उतारें, जबकि कई मिलर्स को अभी तक एफ आर के. उपलब्ध नहीं हो पाया है। जिले में धान खरीद की धीमी रफ्तार को लेकर किसानों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है।

'चुनावी मैदान' निष्पक्ष होता तो हम हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार नहीं हारते, BJP ने हर हथकंडे अपनाएः गौरव गोगोई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रयागराज। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने शुक्रवार को दावा किया कि यदि ''चुनावी मैदान'' निष्पक्ष होता तो उनकी पार्टी को हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार के विधानसभा चुनावों में हार का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में यह आरोप भी लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण, मतदाता सूची में हेरफेर और निर्वाचन आयोग के जरिये चुनाव जीते गए। कांग्रेस नेता ने एक सवाल के जवाब में कहा, ''2024 में मोदी जी ने 400 पार का सपना देखा। उस चुनावी रण में मोदी जी को काफी क्षति हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखेंगे तो पता चलेगा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय थी।'' उनका कहना था, ''अगर चुनाव निष्पक्ष होता और निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होता तो हम हरियाणा, महाराष्ट्र जीतते। इसके बाद जो माहौल बनता उसमें बिहार भी जीतते। फिर केंद्र सरकार एक भी दिन नहीं टिकती।'' गोगोई ने दावा किया कि इसके बाद बीजेपी के मन में खौफ हुआ और हथकंडे अपनाए गए उनका कहना था, ''चुनावी मैदान निष्पक्ष होता तो हम महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार के चुनाव जीतते।'।

जाडों मे जंगलो की सुरक्षा के लिये बढाई गई फारेस्ट कर्मियो की गस्त

जाडों मे जंगलो से लकडी की चोरियो मे होता है इजाफा।

गोला गोकर्णनाथ खीरी। जाडो मे जंगलो के निकटवर्ती गावो मे जंगल की जलौनी लकडी को लोग काटकर तापने व खाना बनाने के लिये ठंडक व कोहरा का फायदा उठाकर लोग काटकर लाते है। जिसके चलते गोला वन क्षेत्राधिकारी संजीव कुमार तिवारी ने वनकर्मियो की चार पांच टीमे गठित कर रात्रिकालीन व शायंकालीन के समय गस्त को बढा दिया है। वही वन क्षेत्राधिकारी गोला संजीव कुमार तिवारी ने बताया की हर हाल मे जंगलो की रक्षा करना हम लोगो का धर्म है। इस दौरान कोई भी लापरवाही बर्दास्त नही की जायागी। गस्त के दौरान कोई भी ब्यक्ति संदिग्ध अवस्था मे जंगलो के आस पास भी मिलता है तो उस पर कडी कारवाई की जायागी।

जंगली जानवरों की बलि चढ़ रहे लखीमपुर खीरी जिले का किसान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखीमपुर खीरी। अगर हम लखीमपुर खीरी जिले में किसानों के हालात देखें तो उनके लिए हिंसक पशुओं किसानी करने में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से लखीमपुर खीरी जिले पर जंगली जानवर आक्रामक हुए हैं उससे किसानो की फसल को तो नुकसान हुआ ही है साथ ही ये उनके पशुधन के लिए खतरा बन गया है। गोला विधान सभा के महेशपुर इलाके के लीलापुर गाँव के 45 वर्षीय ज्ञानू अपने खेत में गन्ने की छिलाई कर रहे थे उनके पास पटाखें और और जलती आग और एक तेज़ धार वाली कुदली नुमे हथियार को साथ लेकर गन्ना छिल रहे थे। हमने उनसे पूछा कि आप इस तरह से क्यों गन्ना छिल रहें हैं तो उन्होंने बताया कि अपनी और अपने पशु की सुरक्षा के लिए आजकल हर ग्रामीण रखता है क्योंकि पता नही कब कोई जंगली जानवर, तेंदुआ, जंगली सूअर या अन्य कोई जानवर हमला कर दे।एक अन्य 22

वर्षीय नौजवान प्रदीप भी पास में ही गन्ना छिल रहे थे वो सभी तेज आवाज और काफी शोर मचा कर गन्ना छिल रहे थे उन्होंने बताया कि पहले हमारे पूर्वजों ने बंदर और भालुओं के डर से खेती छोड़ी और अब लग रहा है हमें अपना खेत भी छोड़ना पड़ेगा उन्होंने कहा- पिछले चार-पांच सालों में जंगली जानवरों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है जबकि सरकार ने इनके नियंत्रण के लिए कुछ भी नहीं किया है। किरतापुर गांव की 50 वर्षीय रामकली ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही आठ किलो आलू बोया था,जिसे बंदरों ने पूरा खोद दिया। जब हम उनसे बात कर ही रहे थे उसी वक्त वहां बंदरों के एक झुंड आ गया जो उनकी फसल को खराब करने लगा। रामकली ने कहा बन्दरों ने हमारा जीना हराम कर दिया है अब वो खेतों से हमारे घरो तक आ गए हैं। हम अपने घर में भी कुछ खाने को रखते हैं वो उसे भी लेकर भाग जाते हैं।इसी तरह ग्राम इमलिया के किसानों ने भी बताया कि उनकी खेती ममरी कस्बे से जंगली सुगर,भालू, बंदर, हाथी उनकी पूरी-पूरी फसलें बर्बाद कर दे रहे हैं। किसानो ने कहा सरकार इनके रोक के लिए तो कुछ नहीं कर रही है बल्कि शहरों से बंदरों को पकड़-पकड़ के गांव के पास जंगलों में छोड़ जा रही है।

हिन्दी की राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता का प्रश्न

आज केवल भाषा का प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि यह सांस्कृतिक स्वाभिमान, बौद्धिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय चेतना से गहराई से जुड़ा हुआ विषय बन चुका है। महात्मा गांधी का यह कथन कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी का प्रयोग देश की उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है, आज भी उतना ही प्रासंगिक और मार्गदर्शक है, जितना स्वतंत्रता संग्राम के काल में था। संविधान ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा अवश्य दिया, किंतु व्यवहारिक धरातल पर उसे जो सम्मान, स्वीकार्यता और व्यापक प्रयोग मिलना चाहिए था, वह आज भी अधूरा है। विडंबना यह है कि अपने ही देश में हिंदी बोलना कई बार कम शिक्षित होने का संकेत मान लिया जाता है, जबकि अंग्रेजी में संवाद करना सामाजिक प्रतिष्ठा और बौद्धिक श्रेष्ठता का प्रतीक समझा जाता है। यह मानसिकता केवल भाषा की उपेक्षा नहीं है, बल्कि उस सांस्कृतिक दासता की अभिव्यक्ति है, जिसकी ओर ब्रिटेन के विचारक वाल्टर कैनिंग ने संकेत करते हुए कहा था कि किसी स्वतंत्र राष्ट्र में विदेशी भाषा का संवाद और शिक्षा की प्रमुख भाषा बने रहना सांस्कृतिक गुलामी का परिचायक है। भारत में अंग्रेजी को राजकाज, प्रशासन, न्याय और उच्च शिक्षा में जो विशेष महत्व प्राप्त है, वह अंग्रेजी की उपयोगिता से अधिक उस मानसिक पराधीनता को उजागर करता है, जो औपनिवेशिक काल की विरासत के रूप में आज भी हमारे भीतर जीवित है।

हिंदी को अपने वास्तविक और स्वाभाविक सम्मान के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा घोषित किए जाने के बाद अपेक्षा थी कि केंद्रीय मंत्रालयों और सरकारी कार्यालयों में इसका व्यापक और प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा, परंतु आज भी स्थिति यह है कि हिंदी के नाम पर कार्यालयों में केवल 'कृपया हिंदी भाषा का प्रयोग करें' जैसे बोर्ड लगाकर औपचारिकता निभा ली जाती है और वास्तविक कामकाज अंग्रेजी में ही संचालित होता है, जो निस्संदेह भारतीय भाषाओं के आत्मसम्मान का अपमान है। हिंदी का प्रश्न केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी इसकी स्वीकार्यता और प्रतिष्ठा का विषय उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोग भी आपस में अंग्रेजी में संवाद कर स्वयं को अधिक आधुनिक और गौरवान्वित अनुभव करते हैं, जबकि हिंदी उनकी सांस्कृतिक पहचान और भावनात्मक जड़ों से जुड़ी भाषा है। संविधान ने हिंदी को सैद्धांतिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया है, किंतु आवश्यकता इस बात की है कि यह यत्र-तत्र-सर्वत्र व्यवहारिक रूप से स्वीकार्य बने और समाज के हर वर्ग द्वारा अपनाई जाए। हिंदी राष्ट्र की सर्वाधिक आत्मसात की गई भाषा है, हालांकि संविधान ने बांग्ला, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, ओड़िया, मराठी सहित 22 भाषाओं को मान्यता दी है और सभी भाषाएं समान रूप से सम्मान की अधिकारी हैं, फिर भी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का स्थान स्वाभाविक रूप से सर्वोपरि है। संविधान के अनुच्छेद 343 (खंड 1) में स्पष्ट किया गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप होगा, इसके बावजूद व्यवहारिक स्तर पर हिंदी को वह स्थान नहीं मिल पाया, जो उसे मिलना चाहिए था।

आज देश में हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या लगभग 45 से 46 प्रतिशत है, जो इसे भारत की सबसे व्यापक भाषा बनाती है, किंतु भौगोलिक विविधता और भाषाई बहुलता के कारण भाषावाद की राजनीति ने हिंदी को कई स्तरों पर नुकसान पहुंचाया है। कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां आज भी यह नहीं चाहतीं कि हिंदी को नैतिक और व्यावहारिक रूप से राजभाषा का समुचित सम्मान मिले, और इस विषय पर संसद तक में विरोध देखने को मिलता है, जबकि इतिहास गवाह है कि स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं ने हिंदी को पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया था और देश के विभिन्न भाषा-भाषी समुदाय आपस में विचार-विमर्श के लिए हिंदी का ही सहारा लेते थे। हिंदी की इसी सार्वभौमिकता और संवाद क्षमता के कारण उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया, किंतु उसकी व्यापकता और गहराई को देखते हुए यह अपेक्षा आज भी जीवित है कि उसे राष्ट्रभाषा का नैतिक सम्मान प्राप्त हो।

हिंदी बहुसंख्यक भारतीयों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा है और इसकी देवनागरी लिपि वैज्ञानिक, सरल और सहज है, जिसमें उच्चारण और लेखन का सीधा संबंध है। हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह विदेशी भाषाओं के शब्दों को बिना किसी संकीर्णता के आत्मसात कर लेती है और इसी कारण वह जीवंत, प्रवाहमयी और समयानुकूल बनी रहती है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हिंदी ने कभी मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द या शब्दावली का बहिष्कार नहीं किया, बल्कि उसे आत्मसात कर अपनी अभिव्यक्ति को और समृद्ध बनाया। शोध अध्ययनों में भी यह तथ्य सामने आया है कि हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में अग्रणी है और भारत की जनसंख्या संरचना के अनुसार यह लगभग 46 प्रतिशत लोगों की भाषा है। इसके बावजूद कुछ लोग अंग्रेजी को भारत की संपर्क भाषा कहने का दुस्साहस करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अंग्रेजी कभी भी देश के आम आदमी की भाषा नहीं रही और न ही हो सकती है।

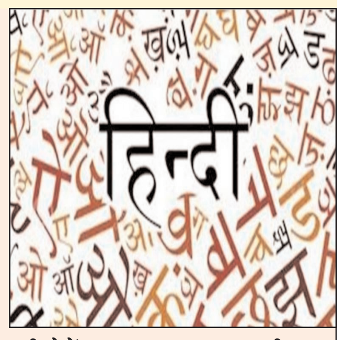

एनी बेसेंट का यह कथन आज भी उतना ही सत्य है कि भारत के विभिन्न प्रांतों में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी सबसे प्रभावशाली बनकर उभरी है और जो व्यक्ति हिंदी जानता है, वह पूरे भारत में सहजता से यात्रा कर सकता है, संवाद कर सकता है और जानकारी प्राप्त कर सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी भारत में अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी को अपनाया है, जो इस बात का प्रमाण है कि हिंदी की व्यावहारिक शक्ति और बाजार में उसकी स्वीकार्यता अत्यंत व्यापक है। यह स्वीकार करना आवश्यक है कि अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है और वैश्विक स्तर पर रोजगार तथा तकनीकी संवाद में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि हिंदी का अपमान या उपेक्षा उचित ठहराई जाए। हिंदी देश की संवेदनशील और भावनात्मक भाषा है, जो राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने और व्यापक वैचारिक विमर्श को संभव बनाने की क्षमता रखती है। आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी को केवल औपचारिकता की भाषा न बनाकर व्यवहार, प्रशासन, शिक्षा, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आत्मविश्वास के साथ स्थापित किया जाए, तभी हिंदी को वह गौरव और सम्मान प्राप्त हो सकेगा, जिसकी वह वास्तविक अधिकारी है।

संजीव ठाकुर

संपादकीय

धुरंधर एक संकेत है हिंदी सिनेमा के बदलाव का

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' सिर्फ एक सफल स्पाई-एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि यह समकालीन हिंदी सिनेमा की उस बदलती प्रवृत्ति का संकेत भी है, जहाँ शोरगुल भरी मार्केटिंग से अधिक भरोसा कंटेंट, प्रस्तुति और दर्शकों की समझ पर किया जा रहा है। बहुत कम प्रचार-प्रसार के बावजूद जिस तरह इस फिल्म ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचा और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया, वह इस बात का प्रमाण है कि अब दर्शक केवल नाम या प्रचार के सहारे नहीं, बल्कि दमदार कहानी और सशक्त अभिनय के आधार पर अपना फैसला लेते हैं। फिल्म की कहानी एक भारतीय जासूस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पाकिस्तान के ल्यारी क्षेत्र में सक्रिय आतंकी नेटवर्क में घुसपैठ करता है।

यह विषय नया नहीं है, लेकिन 'धुरंधर' इसे जिस गंभीरता, परिपक्वता और संतुलन के साथ प्रस्तुत करती है, वही इसे भीड़ से अलग खड़ा करता है। आदित्य धर ने राष्ट्रवाद को न तो अति-भावुक नारेबाज़ी में बदला है और न ही उसे सतही एक्शन तक सीमित रखा है। फिल्म में जासूसी को एक खतरनाक, मानसिक रूप से थका देने वाली और नैतिक दुविधाओं से भरी प्रक्रिया के रूप में दिखाया गया है, जो इसे अधिक विश्वसनीय बनाता है। रणवीर सिंह का अभिनय इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। लंबे समय से एक बड़ी व्यावसायिक सफलता की तलाश में रहे रणवीर को 'धुरंधर' ने वह मंच दिया है, जहाँ वे अपने अभिनय के साथ-साथ अपने स्टारडम को भी नए सिरे से स्थापित कर सके। उनका किरदार न तो पूरी तरह अजेय है और न ही भावनात्मक रूप से सपाट। उसमें डर है, क्रोध है, रणनीति है और सबसे अहम एक ऐसा आंतरिक संघर्ष है, जो दर्शक को उससे जोड़ता है। यह भूमिका रणवीर के करियर की उन चुनिंदा भूमिकाओं में शामिल होती है, जहाँ वे अभिनय और लोकप्रियता के बीच संतुलन साधते नज़र आते हैं। सहायक कलाकारों की मौजूदगी फिल्म को और गहराई देती है। संजय दत्त, आर. माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकारों का चयन केवल नामों के लिए नहीं, बल्कि उनके अभिनय कौशल के लिए किया गया प्रतीत होता है। ये किरदार कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक हैं, न कि केवल नायक की चमक बढ़ाने के लिए। खास बात यह है कि फिल्म में कोई भी चरित्र पूरी तरह काला या सफेद नहीं है; हर किसी के अपने तर्क, अपने डर और अपने स्वार्थ हैं, जो कहानी को अधिक यथार्थवादी बनाते हैं। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े अपने आप में 'धुरंधर' की सफलता की कहानी कहते हैं। पहले दिन लगभग 28 करोड़ की कमाई, पहले तीन दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करना और पहले हफ्ते में भारत में 200 करोड़ से अधिक का नेट कलेक्शन ये सब उस दौर में हुआ है, जब दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाना आसान नहीं माना जाता। वर्ल्डवाइड 300 करोड़ से अधिक की कमाई ने यह साफ कर दिया कि फिल्म की अपील केवल घरेलू दर्शकों तक सीमित नहीं है। इसने कई बड़ी और बहुप्रचारित फिल्मों के पहले दिन, शुरुआती दिनों और यहां तक कि लाइफटाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिए। यह सफलता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस धारणा को चुनौती देती है कि बिना आक्रामक मार्केटिंग के कोई फिल्म बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो सकती। 'धुरंधर' की सफलता बताती है कि अगर फिल्म का कंटेंट मजबूत हो, तो दर्शक खुद उसका प्रचार करते हैं। सोशल मीडिया पर चर्चाएं, माउथ पब्लिसिटी और समीक्षकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने मिलकर इस फिल्म को एक आंदोलन जैसा बना दिया। यह हिंदी फिल्म उद्योग के लिए एक सीख है कि शायद अब बजट का बड़ा हिस्सा प्रचार पर खर्च करने की बजाय लेखन, निर्देशन और अभिनय पर लगाना अधिक सार्थक हो सकता है। रणवीर सिंह के करियर के संदर्भ में 'धुरंधर' एक निर्णायक मोड़ की तरह है। हाल के वर्षों में उनकी कुछ फिल्मों के औसत या कमजोर प्रदर्शन के बाद यह फिल्म उन्हें फिर से शीर्ष सितारों की पंक्ति में खड़ा करती है। यह साबित करती है कि स्टारडम केवल छवि या ऊर्जा से नहीं, बल्कि सही स्क्रिप्ट के चयन और खुद को कहानी के अनुरूप ढालने की क्षमता से टिकता है।

'धुरंधर' ने रणवीर को न सिर्फ व्यावसायिक सफलता दी है, बल्कि उनके अभिनय पर लगे कुछ सवालों का भी ठोस जवाब दिया है। फिल्म का व्यापक प्रभाव यह भी है कि इसने 2025 की फिल्मों की दौड़ में मानक ऊंचे कर दिए हैं। कम समय में इतने बड़े आंकड़े छूना और कई स्थापित फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ना इस बात का संकेत है कि दर्शक अब गुणवत्ता को प्राथमिकता दे रहे हैं। 'धुरंधर' केवल एक हिट फिल्म नहीं, बल्कि यह उस बदलाव का प्रतीक है, जहाँ हिंदी सिनेमा धीरे-धीरे दिखावे से निकलकर सार की ओर लौटता दिखाई दे रहा है। अंततः 'धुरंधर' की सफलता इस विश्वास को मजबूत करती है कि सिनेमा अभी भी समाज से संवाद करने का एक सशक्त माध्यम है। जब कहानी ईमानदार हो, निर्देशन स्पष्ट हो और अभिनय विश्वसनीय हो, तब बिना शोर के भी फिल्म इतिहास रच सकती है। 'धुरंधर' इसी विश्वास का जीवंत उदाहरण है एक ऐसी फिल्म जो न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर जीती है, बल्कि हिंदी सिनेमा की दिशा पर भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करती है।

महेन्द्र तिवारी

जामताड़ा अब इतिहास: साइबर ठगी का नया अड्डा आपके आसपास

[साइबर अपराध का विकेंद्रीकरण: शहरों से गांव तक]
[डिजिटल इंडिया और साइबर अपराध: ग्रामीण क्षेत्र में फैलता संकट]

साइबर अपराध अब किसी शहर या जिले तक सीमित नहीं रहा। कभी झारखंड का जामताड़ा साइबर ठगी का पर्याय बन चुका था। वहां से निकलने वाली फिशिंग कॉल्स, फर्जी निवेश योजनाओं और बैंक डिटेल्स चुराने के मामलों की खबरें पूरे देश में चर्चा का विषय बनती थीं। लेकिन आज यह खतरा केवल बड़े शहरों या साइबर हब तक सीमित नहीं रहा। ग्रामीण भारत में भी इसका दायरा तेजी से बढ़ गया है। हाल ही में मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के छोटे से घटवा गांव से दो युवकों की गिरफ्तारी ने यह सच फिर साबित कर दिया कि साइबर ठगी अब शहरों और बड़े कस्बों तक सीमित नहीं है। दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ये युवक कथित रूप से बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा थे। यह घटना न केवल स्थानीय स्तर पर चिंता का विषय है, बल्कि पूरे देश में साइबर अपराध के विकेंद्रीकरण का भी संकेत देती है। जामताड़ा, जो कभी साइबर फ्रॉड का हब माना जाता था, अब पांचवें स्थान पर खिसक चुका है। पहले यहां युवा लोगों को लुभाकर बैंक डिटेल्स मांगते, फर्जी निवेश योजनाओं या लॉटरी जीत का झांसा देकर ठगते थे। लेकिन अब यह प्रवृत्ति बदल गई है। उत्तरी भारत के छोटे कस्बे और जिले, जैसे हरियाणा का मेवात, राजस्थान के भारतपुर और मथुरा, बिहार के गोपालगंज, झारखंड के देवघर और धनबाद, अब साइबर ठगी के नए हब बन गए हैं। यहां तक कि आईटी और कॉरपोरेट हब गुरुग्राम में भी यह अपराध तेजी से फैल रहा है।

ये नए हब जामताड़ा मॉडल की तरह काम करते हैं। युवा समूह बनाकर, फर्जी ऐप्स, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे गरीबी और बेरोजगारी का फायदा उठाकर युवाओं को ठगी के नेटवर्क में शामिल कर लेते हैं। देवघर जिले में फर्जी कॉल सेंटर्स की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है और यह जामताड़ा को पीछे छोड़ चुका है। अब ग्रामीण क्षेत्र भी इस जाल में फंस रहे हैं, जहां कई लोग अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग करके आसानी से अपराध में शामिल हो जाते हैं।

ग्रामीण भारत में साइबर ठगी का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका है। मप्र के बड़वानी जिले के घटवा गांव की हालिया घटना ग्रामीण भारत में साइबर ठगी के बदलते चेहरे का ताजा उदाहरण है। यह गांव ठीकरी तहसील में स्थित है, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आता है। यहां के दो युवकों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कथित रूप से साइबर फ्रॉड नेटवर्क में शामिल थे। इनके अपराध केवल स्थानीय नहीं थे; इनके झांसे में आए पीड़ितों का प्रभाव दिल्ली और अन्य बड़े शहरों तक फैला था। मध्यप्रदेश में 2021 से 2025 तक साइबर ठगी के मामलों का आंकड़ा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है, जबकि रिकवरी रेट केवल 0.2% है। बड़वानी जिले में हाल ही में 82,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें ठग ने खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर पीड़ित को डराया। साइबर ठगी अब शहरों से बाहर निकलकर गांवों में भी फैल चुकी है। ग्रामीण युवा स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए इसमें आसानी से शामिल हो रहे हैं, लेकिन कानूनी जागरूकता की कमी उन्हें गंभीर जोखिम में डाल रही है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में यह भी सामने आया कि कई

नेटवर्क विदेशों तक फैले हुए हैं, जैसे म्यांमार, जहां युवाओं को फ्रॉड नेटवर्क में ट्रैफिक किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया की सफलता ने इंटरनेट को हर कोने तक पहुंचा दिया, लेकिन साइबर सुरक्षा शिक्षा पीछे रह गई। ई-कॉमर्स, डिजिटल वॉलेट्स और क्रिप्टो जैसी नई तकनीक ने ठगों को नए अवसर दिए। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में साइबर क्राइम में 31.2% की वृद्धि हुई। बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में 17,000 से अधिक मामले दर्ज हुए, लेकिन छोटे कस्बे जैसे भरतपुर और नूह अब शीर्ष स्थान पर हैं। साइबर ठगी के प्रभाव अब केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहे। लाखों लोग अपनी मेहनत की कमाई खो रहे हैं, उनके सपने, भविष्य और आर्थिक सुरक्षा खतरे में हैं। नए स्कैम्स, जैसे 'डिजिटल अरेस्ट', अब लोगों को घर पर 'अरेस्ट' दिखाकर डराने की तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मानसिक तनाव और सामाजिक कलंक बढ़ रहा है। यह केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, बल्कि समाज और देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना पर भी गंभीर असर डाल रहा है। समाधान की दिशा में पुलिस सक्रिय हो रही है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में 800 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया और कई फर्जी कॉल सेंटर्स को बंद किया। लेकिन यह केवल शुरुआत है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जागरूकता की बेहद आवश्यकता है। सरकार को साइबर सुरक्षा शिक्षा और प्रशिक्षण को व्यापक स्तर पर लागू करना होगा, कड़े कानून बनाने होंगे, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना होगा ताकि अपराधियों की जड़ें कमजोर हों। सकारात्मक पहल के रूप में, इंश्योरेंस कंपनियां अब साइबर फ्रॉड कवर देने लगी हैं, जो पीड़ितों के लिए राहत और सुरक्षा का जरिया बन सकता है। मप्र के बड़वानी जिले के घटवा गांव की घटना एक गंभीर चेतावनी है, साइबर ठगी अब जामताड़ा की मोनोपॉली नहीं रही। यह पूरे देश में फैल चुकी है, और अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह एक महामारी का रूप ले सकती है। इस जाल से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है – व्यापक जागरूकता, साइबर शिक्षा और वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करना। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना अब हर नागरिक की जिम्मेदारी बन गई है। जामताड़ा अब इतिहास बन चुका है, और साइबर ठगी का नया ठिकाना अब आपका अपना गांव है। यदि हम अभी नहीं चेते, तो बहुत देर हो जाएगी, और कीमत हमारी सुरक्षा और भविष्य को चुकानी पड़ेगी।

प्रो. आरके जैन

राजस्थान में बम धमकियों का साया और सिस्टम की बेबसी

राजस्थान में पिछले एक वर्ष से बम से उड़ाने की धमकियों का जो सिलसिला चला आ रहा है, उसने न केवल पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ाई है बल्कि आम नागरिकों के मन में भी भय और असुरक्षा की गहरी भावना भर दी है। हाईकोर्ट, स्कूल, होटल, अस्पताल, स्टेडियम और अन्य सार्वजनिक स्थलों को बार-बार उड़ाने की धमकियां मिलना अब एक सामान्य खबर बनती जा रही हैं। जयपुर जैसे शांत शहर का देश के उन बड़े महानगरों में शुमार होना, जहां सबसे ज्यादा धमकी भरे ईमेल और संदेश आए हैं, यह संकेत देता है कि समस्या केवल कानून-व्यवस्था की नहीं बल्कि तकनीक और सुरक्षा के बीच बढ़ती खाई की है।राजस्थान में अब तक 61 से अधिक धमकियां दर्ज की जा चुकी हैं। जयपुर एसएमएस स्टेडियम को सात बार और अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को चार बार उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। सबसे ज्यादा ईमेल निजी स्कूलों को भेजे गए, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों में दहशत फैल गई। हर बार पुलिस, बम निरोधक दस्ता और प्रशासन अलर्ट पर आया, पूरे परिसर की तलाशी ली गई, यातायात रोका गया और आम जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन हर बार नतीजा शून्य ही रहा। न बम मिला, न कोई ठोस सुराग।यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन धमकियों का औचित्य क्या है। क्या यह किसी शरारती तत्व का मजाक है, जो सिस्टम को छकाने में आनंद ले रहा है, या फिर यह किसी बड़े आतंकी षड्यंत्र की तैयारी का हिस्सा है, जिसमें बार-बार चेतावनी देकर सुरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया को परखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि हर धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आतंकवाद का इतिहास यही बताता है कि कई बार झूठी सूचनाओं की आड़ में असली हमले को अंजाम दिया गया है। राजस्थान पुलिस और इंटेलिजेंस की मुश्किलें यहां से शुरू होती हैं। अधिकतर धमकियां ईमेल के जरिए भेजी जा रही हैं, जिनका स्रोत पता करना तकनीकी रूप से बेहद जटिल है। आईपी एड्रेस और लोकेशन को छुपाने वाले आधुनिक टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन के माध्यम से भेजे गए ईमेल और मैसेज किसी भी वास्तविक भौगोलिक पहचान को सामने नहीं आने देते। न मोबाइल नंबर की जरूरत, न सिम कार्ड, न स्थायी इंटरनेट कनेक्शन। केवल एक लैपटॉप या मोबाइल और एक मजबूत वीपीएन पर्याप्त है। वीपीएन तकनीक मूल रूप से ऑनलाइन निजता और सुरक्षा के लिए विकसित की गई थी, ताकि उपयोगकर्ता अपने डेटा को हैकिंग और निगरानी से बचा सके। लेकिन आज यही तकनीक अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित ढाल बन चुकी है। जितना महंगा वीपीएन, उतनी ज्यादा सुरक्षा और उतनी ही कम संभावना कि कोई सुराग हाथ लगे। कई वीपीएन कंपनियों के सर्वर यूरोप और मध्य-पूर्व के देशों में स्थित हैं, जहां डेटा संरक्षण के कानून बेहद सख्त हैं। यूएई और यूरोप में वीपीएन का उपयोग बहुत आम है और वहां की कंपनियां यूजर डेटा साझा करने में तब तक सहयोग नहीं करतीं, जब तक संबंधित देश की अदालत से औपचारिक आदेश न मिले। यही वजह है कि भारतीय जांच एजेंसियों के हाथ बंधे नजर आते हैं। किसी विदेशी वीपीएन सर्वर से डेटा मंगवाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें समय लगता है और तब तक अपराधी अपनी पहचान बदल चुका होता है या नया फर्जी ईमेल अकाउंट बना लेता है। कई ऐसे सर्वर और ईमेल सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनसे भेजा गया संदेश कुछ ही समय में स्वतः डिलीट हो जाता है और डिजिटल फुटप्रिंट लगभग समाप्त हो जाता है। दिल्ली एनसीआर में अब तक 300 से ज्यादा धमकियां, मुंबई में 64, हैदराबाद में 85, बेंगलुरु में 123 और जयपुर में 61 धमकियों का आंकड़ा बताता है कि यह समस्या केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। यह एक राष्ट्रीय चुनौती बन चुकी है। बावजूद इसके, पुलिस और खुफिया एजेंसियां हर बार केवल बम की जांच तक सीमित रह जाती हैं। उन्हें हर धमकी को गंभीर मानते हुए सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है, लेकिन अपराधी तक पहुंचने के लिए ठोस तकनीकी और कानूनी साधनों का अभाव साफ दिखाई देता है। इस स्थिति में आम जनता के मन में यह धारणा बनना स्वाभाविक है कि पुलिस बेबस है। हालांकि सच्चाई यह है कि पुलिस और इंटेलिजेंस के सामने तकनीक की रफ्तार और अंतरराष्ट्रीय कानूनों की सीमाएं एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी हैं। साइबर अपराध अब किसी एक राज्य या देश की सीमा में बंधा नहीं रहा। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश के सर्वर से तीसरे देश को धमकी दे सकता है और चौथे देश की एजेंसियां उसे ढूंढने में लगी रह जाती हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय इसी गंभीरता को दर्शाता है। हाईकोर्ट न केवल न्याय का प्रतीक है बल्कि लोकतंत्र की एक मजबूत

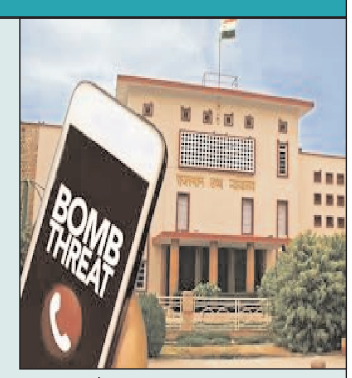

संस्था भी है। उस पर बार-बार धमकी आना पूरे सिस्टम को चुनौती देने जैसा है। अतिरिक्त सुरक्षा बल, आधुनिक निगरानी उपकरण और कड़े प्रवेश नियम तत्काल जरूरत हैं, लेकिन दीर्घकालीन समाधान केवल भौतिक सुरक्षा से नहीं निकलेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी उजागर कर दिया है कि भारत को अपनी साइबर फॉरेंसिक क्षमता को और मजबूत करना होगा। केवल विदेशी सर्वरों पर निर्भर रहने की बजाय देश में ऐसे तकनीकी ढांचे विकसित करने होंगे, जो रियल-टाइम ट्रैकिंग, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और तेज कानूनी प्रक्रियाओं को संभव बना सकें। साथ ही, वीपीएन और फर्जी ईमेल सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर सख्त नियमों और समझौतों की जरूरत है। यह भी जरूरी है कि हर धमकी को केवल अफवाह या मजाक मानकर नजरअंदाज न किया जाए, लेकिन साथ ही जनता में अनावश्यक दहशत फैलने से भी बचाया जाए। जिम्मेदार सूचना, पारदर्शिता और भरोसे का वातावरण बनाना प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों पर बार-बार खाली कराने से जनजीवन प्रभावित होता है और यही शायद उपद्रवियों का असली मकसद भी हो सकता है, सिस्टम को थकाना और लोगों के मन में डर बैठाना। आखिरकार यह सवाल अनुत्तरित ही रह जाता है कि क्या यह किसी शरारती दिमाग का खेल है या किसी गहरी साजिश की तैयारी। जब तक एक भी अपराधी पकड़ा नहीं जाता, तब तक यह आशंका बनी रहेगी। राजस्थान पुलिस और खुफिया एजेंसियां मजबूर जरूर दिखती हैं, लेकिन यह मजबूरी तकनीक और कानून की सीमाओं से उपजी है, न कि इच्छाशक्ति की कमी से। जरूरत है इन सीमाओं की, ताकि धमकी देने वाले यह न समझें कि वे हमेशा कानून की पहुंच से बाहर रहेंगे।

कांतिलाल मांडोत

भारत गौरव अवार्ड-2025 से सम्मानित हुए वरिष्ठ पत्रकार के.पी. मलिक

देश के प्रतिष्ठित संस्थान काली रमन फाउंडेशन द्वारा इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित 11वें रहबर-ए-आज़म सर छोटू राम मेमोरियल 'भारत गौरव अवार्ड-2025' समारोह में इस वर्ष विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया। शिक्षा, राजनीति, स्वास्थ्य, खेल और समाजसेवा के साथ-साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तित्व भी इस सम्मान के पात्र बने। इन्हीं में शामिल रहे वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक के.पी. मलिक, जिन्हें उनकी बेबाक़ और निर्भीक पत्रकारिता के लिए 'भारत गौरव सम्मान-25' से नवाज़ा गया। समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए के.पी. मलिक ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज और देश के प्रति कर्तव्य निर्वहन की नई प्रेरणा है। उन्होंने आयोजक संस्था का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज की सच्ची आवाज़ बनना और पीड़ितों की बात सत्ता के केंद्र तक पहुँचाना है, जिसे वह हमेशा निभाते रहेंगे।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले के आदमपुर गाँव में जन्मे कुंवर पाल मलिक, जिन्हें पत्रकारिता जगत में के.पी. मलिक के नाम से जाना जाता है, ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली को कर्मभूमि बनाया। गांव के संस्कारों और किसान परिवार की सादगी से निकला यह युवा धीरे-धीरे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों का जाना-माना नाम बन गया। मलिक के लेखों और रिपोर्ट्स में किसानों, गरीबों, मजदूरों और वंचितों की समस्याएँ लगातार प्रमुख स्थान पाती रही हैं, जिसके चलते उन्हें जनपक्षधर पत्रकार माना जाता है। अपने बेबाक़ लेखन और निर्भीक रिपोर्टिंग के कारण के.पी. मलिक न केवल दिल्ली की पत्रकारिता दुनिया में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त और सम्मानित आवाज़ बन चुके हैं। संसद की रिपोर्टिंग में उनका लंबा अनुभव है और वर्ष 2001 में हुए संसद हमले की कवरेज के दौरान वह चश्मदीद गवाह भी रहे। मीडिया के अधिकारों और पत्रकारों की सुरक्षा के मुद्दों पर भी वह हमेशा अग्रसर रहते हैं। कैरियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने दूरदर्शन, बीबीसी टीवी, जी न्यूज, सहारा समय और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। बाद में दैनिक भास्कर से जुड़कर उन्होंने राजनीतिक संपादक के रूप में अपनी पहचान को और अधिक मजबूत किया। पिछले वर्ष उन्हें 'अटल रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' और 'मुंशी प्रेमचंद सम्मान' से भी नवाज़ा गया था। पत्रकारिता के साथ-साथ मलिक समाजसेवा में भी सक्रिय रहते हैं। अपने व्यस्त समय के बावजूद वह अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और अक्सर गाँव जाकर खेती-किसानी और ग्रामीण समस्याओं को समझते हैं। उनके लेखों में यह जुड़ाव साफ झलकता है।

दिल्ली में रहते हुए भी उनकी पहचान एक जमीन से जुड़े, सरल और सच्चे पत्रकार की है, जिनकी प्रतिबद्धता युवा पत्रकारों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। 'भारत गौरव अवार्ड-2025' से सम्मानित होना के.पी. मलिक के लंबे और समर्पित पत्रकारिता सफर की स्वाभाविक उपलब्धि मानी जा रही है, जिसने देशभर में उनकी प्रतिष्ठा को और अधिक मज़बूत किया है।

अशोक कुमार निर्भय

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः**-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0 -9511151254, E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

अजरबैजान भेजने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, एक करोड़ से ज्यादा की ठगी, 100 से अधिक युवा लुटे

लालगंज (रायबरेली)। विदेश में नौकरी का सपना दिखाकर युवाओं को लूटने वाला एक बड़ा ठग गिरोह सामने आया है। कोतवाली क्षेत्र के डलमऊ रोड पर संचालित फर्जी कंपनी ने अजरबैजान में नौकरी दिलाने के नाम पर एक सौ से अधिक युवाओं से एक करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ऐंठ ली।आरोप है कि कंपनी संचालकों ने इलेक्ट्रिशियन, शटरिंग और फूड पैकेजिंग जैसी नौकरियों का झांसा देकर युवाओं को अपने जाल में फंसाया। किसी से 90 हजार तो किसी से डेढ़ लाख रुपये तक वसूले गए। भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने पासपोर्ट, वीजा और हवाई टिकट तक थमा दिए, जो पूरी तरह फर्जी निकले।ठगों ने करीब 40 युवकों को दिल्ली एयरपोर्ट तक भेज दिया। एयरपोर्ट पर दस्तावेजों की जांच हुई तो हड़कंप मच गया। सभी कागजात जाली पाए गए और युवाओं को विदेश जाने से रोक दिया गया। तब जाकर युवकों को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ।पीड़ितों का आरोप है कि ठगी का मुख्य आरोपी गोरखपुर का रहने वाला है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्य रायबरेली और फतेहपुर के बताए जा रहे हैं। यह गिरोह लंबे समय से बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाकर ठगी कर रहा था।सबसे गंभीर बात यह है कि पीड़ित युवकों ने पहले ही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने से ठगों के हौसले बुलंद रहे। मजबूर होकर पीड़ितों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी।अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी ठगी कैसे होती रही और पुलिस को भनक तक क्यों नहीं लगी? पीड़ितों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और ठगी की रकम वापस दिलाने की मांग की।

जल निगम द्वारा पानी आपूर्ति के लिए डाली गई मुख्य पाइप लाइन पांच जगहों से टूटी

महराजगंज रायबरेली- सलेथू रजबहा नहर पर नरई बाजार के पास लोकनिर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा पुल निर्माणाधीन है। पुल बनाने के लिए जेसीबी मशीन द्वारा की गई खुदाई में जल निगम द्वारा पानी आपूर्ति के लिए डाली गई मुख्य पाइप लाइन पांच जगहों से टूट गई है। जिससे नरई, डीहा, महापतगंज, ईशागंज, पूरे तिवारी समेत लगभग आधा दर्जन गांवों के लोगों की जलापूर्ति बाधित है। जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। नरई गांव निवासी बिन्नू सिंह, रामू सिंह, बबलू पासवान, आदि का कहना है कि पुल निर्माण के लिए की गई खुदाई में पाइप लाइन पांच जगहों से टूट गई है जिससे कई दिनों से लोगों को जलापूर्ति बाधित है।

स्पा सेंटर पर एयरटेल कर्मी पर बेसबॉल बैट से जानलेवा हमला, तीन पर केस दर्ज

रायबरेली। शहर के बरगद चौराहा के पास स्थित एक स्पा सेंटर में शुक्रवार देर शाम उस समय सनसनी फैल गई जब एयरटेल कंपनी के सेल एक्सीक्यूटिव को वाई-फाई शिकायत के बहाने बुलाकर बेरहमी से पीट दिया गया। आरोप है कि स्पा संचालक और उसके साथियों ने बेसबॉल बैट से हमला किया।पीड़ित सत्यम तिवारी सरेनी थाना क्षेत्र के छमनीखेड़ा के निवासी हैं और एयरटेल कंपनी में सेल एक्सीक्यूटिव के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि स्पा संचालक शैलेंद्र ने वाई-फाई खराब होने की शिकायत कर उन्हें बुलाया था। शाम करीब सवा आठ बजे जैसे ही वह स्पा सेंटर पहुंचे, संचालक ने गाली-गलौज शुरू कर दी और वाई-फाई खराब होने का आरोप लगाते हुए बेसबॉल बैट से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।पीड़ित के सिर पर हेलमेट होने के कारण जान बच गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिर पड़े। शोर सुनकर पास की लाइब्रेरी में पढ़ रहे युवकों ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल कर्मचारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।शहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक शिव शंकर सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर स्पा संचालक सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है और मामले की जांच जारी है।

नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐहार में अव्यवस्था, घंटों बंद रहता है अस्पताल का गेट

● गेट बंद, मरीज परेशान: ऐहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्था

चार लोगों के स्टाप में दो ही रहते मौजूद, अन्य छुट्टी पर या इमरजेंसी में...

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐहार में व्याप्त अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों को रोजाना गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल का गेट निर्धारित समय पर नहीं खोला जाता, जिससे इलाज के लिए आने वाले मरीजों को घंटों बाहर इंतजार करना पड़ता है।मरीजों और उनके तीमारदारों का कहना है कि कई बार गंभीर हालत में पहुंचे मरीजों को भी गेट बंद मिलने के कारण तत्काल उपचार नहीं मिल पाता, जिससे उनकी स्थिति और बिगड़ जाती है। केंद्र में चार कर्मचारियों की तैनाती होने के बावजूद केवल आयुष चिकित्सक और एक वार्डबॉय ही ड्यूटी पर मौजूद मिले। ग्रामीणों का कहना है कि इनके भी समय पर न आने-जाने से अस्पताल की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि अस्पताल को निर्धारित समय पर खोला जाए तथा लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि मरीजों को समय पर उपचार मिल सके।मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायबरेली से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन न उठने के कारण उनसे बात नहीं हो सकी।

जेडक्स पैरेंट्रल प्राइवेट लिमिटेड ने नए आईवी फ्लूड उत्पादों का किया भव्य शुभारंभ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के बाराबंकी जनपद के छतेना गढ़ी क्षेत्र में स्थित जेडक्स पैरेंट्रल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने नए उत्पाद टूपोर्ट और सिंगल पोर्ट आईवी फ्लूड बोतल का भव्य शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम लखनऊ के गोमती नगर स्थित ग्रैंड छ्व्क्क होटल में आयोजित हुआ। इस अवसर पर कंपनी के निदेशकगण जितेंद्र पाल सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, भानु प्रताप सिंह एवं पूर्णिमा सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कंपनी के मजबूत स्तंभ सीए धर्मेंद्र कुमार सिंह द्वारा नए उत्पादों का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस आयोजन में भारत के विभिन्न राज्यों एवं विश्व के विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों एवं अतिथियों ने भाग लिया, जिससे कार्यक्रम को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। इसके साथ ही कंपनी की 33 सदस्यीय मार्केटिंग टीम भी कार्यक्रम में उपस्थित रही, जिसका नेतृत्व अनिल कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। गौरतलब है कि जेडक्स पैरेंट्रल प्राइवेट लिमिटेड भारत में सबसे अधिक आईवी फ्लूड बोतलों का निर्माण करने वाली पहली कंपनी बन गई है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। कंपनी प्रबंधन ने बताया कि नए उत्पाद उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं और मरीजों की सुरक्षा व सुविधा को ध्यान में रखते हुए विकसित किए गए हैं।

डीएम ने किया सीएचसी रेउसा का औचक निरीक्षण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर: जिलाधिकारी (डीएम) डॉ. राजागणपति आर. ने शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) रेउसा का औचक निरीक्षण कर वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी, लेबर रूम, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी (एचआरपी) रजिस्टर, कोल्ड चेन कक्ष, टीकाकरण काउंटर, नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (एनबीएसयू) वार्ड, कंगारू मदर केयर (केएमसी) वार्ड सहित विभिन्न कक्षों और अभिलेखों का गहन निरीक्षण किया।

साफ़-सफ़ाई और बेडशीट पर कड़ी फटकार

निरीक्षण के दौरान डीएम ने अस्पताल परिसर में साफ-सफाई न होने और बेडशीट गंदी पाए जाने पर कड़ी नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने यह भी पाया कि बेडशीट कलर कोडिंग के अनुसार नहीं बिछी हुई थीं। उन्होंने प्रभारी चिकित्साधिकारी (एमओआईसी) से चिकित्सक, फार्मासिस्ट, नर्स और सफाई कर्मचारियों की जानकारी ली।

एचआरपी रजिस्टर और ड्यूटी रजिस्टर में गंभीर कमियां

डीएम ने प्रभारी चिकित्साधिकारी पर हाई रिस्क प्रेग्नेंसी (एचआरपी) रजिस्टर में गंभीर कमी पाए जाने पर नाराज़गी व्यक्त की और जल्द से जल्द सुधार के निर्देश दिए। इसके साथ ही, उन्होंने कर्मचारियों के लिए ड्यूटी रजिस्टर बनाने का निर्देश भी दिया।

लापरवाही पर हुई कार्रवाई

अभिलेखों और कार्य में कमी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित स्टाफ के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए: फैमिली काउंसलर ज्ञान देवी: रजिस्टर में कमी मिलने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

स्टाफ नर्स आकाशिता: चेतावनी पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया।

स्टाफ नर्स सीमा: रजिस्टर में कमी पाए जाने पर 15 दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया।

प्रभारी चिकित्साधिकारी: रजिस्टर एवं अन्य कमियां मिलने पर स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया गया।

मरीजों से की बात

डीएम ने एनबीएसयू वार्ड के रजिस्टर का अवलोकन किया और रेफर किए गए मरीज से दूरभाष के माध्यम से वार्ता कर उनका हाल जाना। जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) वार्ड के निरीक्षण के दौरान, उन्होंने भर्ती मरीजों से बातचीत कर उन्हें दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) डॉ. सुरेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार लाने और मरीजों को बेहतर सुविधाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

5.58 करोड़ का पंचायत घोटाला: ऑडिट से भागते सचिव, रिकॉर्ड गायब और 33 पर गिरी गाज

● यदि एक ही वित्तीय वर्ष में पंचायत स्तर पर रिकॉर्ड गायब हैं, तो 2023-24 और 2024-25 में कराए गए कार्यों की स्थिति क्या है?

गोंडा। जनपद की ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर सरकारी धन की खुली लूट का एक और बड़ा मामला सामने आया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कराए गए कार्यों के ऑडिट के दौरान 5 करोड़ 58 लाख रुपये के घोटाले की आशंका ने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। ऑडिट टीम के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत न कर पाने पर 33 ग्राम पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किया गया है, वहीं समय से जवाब न देने की स्थिति में रिकवरी और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई है।

ऑडिट पहुंचा, तो फाइलें हो गई गायब

सूत्रों के अनुसार जिन पंचायतों में बड़े पैमाने पर कार्य कराए जाने का दावा किया गया था, वहां ऑडिट टीम के पहुंचते ही न तो मस्टर रोल मिले, न वाउचर, न तकनीकी स्वीकृति और न ही भुगतान से जुड़े ठोस दस्तावेज। यही नहीं, कई पंचायतों में प्रधान और सचिव दोनों ही संतोषजनक जवाब देने से बचते नजर आए। प्रशासनिक अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि रिकॉर्ड उपलब्ध न कराना सीधे-सीधे वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करता है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कहीं 10 तो कहीं 15 लाख तक का हिसाब गायब

जांच में सामने आया है कि कुछ पंचायतों में 10 से 15 लाख रुपये तक का कोई लेखा-जोखा नहीं मिला। जिन कार्यों को कागजों में पूर्ण दिखाया गया, वे या तो धरातल पर हुए ही नहीं या फिर बेहद घटिया गुणवत्ता के पाए गए। यह स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि पंचायत स्तर पर योजनाओं को एटीएम समझकर पैसा निकाला गया और आपसी बंदरबांट कर ली गई।

इन पंचायतों पर गड़बड़ी की सबसे अधिक आशंका

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार जिन पंचायतों में रिकॉर्ड न देने और गड़बड़ी की आशंका जताई गई है, उनमें शामिल हैं– अधियारिया बुजुर्ग, बक्सरिया ग्रांट, बीरपुर, कादीपुर, करनवा, पिपरी, अकबरपुर, कुंदरखा, पंचराही, मनोराजोत, पुरैसखरी, कटुआ नाला, रायपुर फकीर, माधोपुर, धनुही, पूरे पहाड़ा, दुबहरपुर, पृथ्वीपालगढ़ ग्रांट, मध्यानगर, श्रीनगर, बरडिहा, सिंघापुर, सिमई, बहलोलपुर, तुर्कडीहा, मलारी, उकरा, तुलसीपुर कोड़री, कफिया, सोहिया, गड़ही, बखरवा, तुर्कडीहा, गणेशपुर ग्रांट और चंदा सहित अन्य पंचायतें शामिल हैं।

प्रशासन का सख्त रुख

डिप्टी जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) लालजी दुबे ने स्पष्ट किया है कि– 'संबंधित 33 सचिवों से एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि संतोषजनक जवाब और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए, तो सचिव और प्रधान दोनों को दोषी मानते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी धन की रिकवरी भी कराई जाएगी।'

सवालों के घेरे में पंचायत व्यवस्था

यह मामला केवल कुछ पंचायतों तक सीमित नहीं माना जा रहा। जानकारों का कहना है कि यह पूरे जिले की पंचायत व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है–

क्या बिना भौतिक सत्यापन के भुगतान किए गए?

क्या तकनीकी स्वीकृतियां सिर्फ कागजी औपचारिकता बनकर रह गईं?

क्या ब्लॉक और जिला स्तर पर निगरानी तंत्र पूरी तरह विफल रहा?

जनता पूछ रही है जवाब

गांवों में रहने वाली आम जनता अब खुलकर सवाल कर रही है– 'जब कागजों में सड़क, नाली, हैंडपंप और इंटरलॉकिंग बन गई, तो गांव आज भी बदहाल क्यों है?'

यह घोटाला केवल पैसों का नहीं, बल्कि जनता के भरोसे का भी है, जो सरकार और पंचायत प्रतिनिधियों पर किया गया था।

अब आगे के वर्षों पर भी उठे गंभीर सवाल

वर्ष 2022-23 में करोड़ों रुपये की अनियमितता सामने आने के बाद यह सवाल और गहरा हो गया है कि यदि एक ही वित्तीय वर्ष में पंचायत स्तर पर रिकॉर्ड गायब हैं, तो 2023-24 और 2024-25 में कराए गए कार्यों की स्थिति क्या है?

सूत्रों का कहना है कि जिन पंचायतों में 2022-23 के दौरान ऑडिट में गड़बड़ी पकड़ी गई, उन्हीं पंचायतों में बाद के वर्षों में भी उसी कार्यशैली से भुगतान किए गए हैं। ऐसे में यदि इन वर्षों की भी गहन जांच कराई गई, तो घोटाले का आंकड़ा और अधिक बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि सिर्फ एक वर्ष तक जांच सीमित रखना पर्याप्त नहीं होगा। यदि सरकार और जिला प्रशासन वास्तव में पारदर्शिता चाहता है, तो वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25– तीनों वित्तीय वर्षों के सभी पंचायत कार्यों की समग्र, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए।

आगे क्या? अब निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि यह मामला केवल नोटिस और औपचारिक जवाब तक सीमित रहा, तो यह भ्रष्टाचार को मौन स्वीकृति होगी। लेकिन यदि रिकवरी, निलंबन और एफआईआर तक कार्रवाई पहुंचती है, तो यह पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक निर्णायक प्रहार साबित होगा।

फिलहाल इतना तय है— ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर लूट का यह मामला अब दबने वाला नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है।

रबी सीजन में उर्वरक वितरण पर सख्ती तीन दुकानदारों को नोटिस

ज्ञानपुर। रबी सीजन में गेहूं की टॉपड्रेसिंग को ध्यान में रखते हुए जिला कृषि अधिकारी कुमारी इरम ने जनपद भदोही में उर्वरक प्रतिष्ठानों एवं सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर तीन उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निरीक्षण में नागमलपुर सहकारी समिति पर रेट बोर्ड पर उर्वरक का मूल्य अंकित न होने, एग्री जंक्शन किसान सेवा केंद्र पर रजिस्टर में ग्राहकों के मोबाइल नंबर दर्ज न किए जाने तथा पाण्डेय खाद भंडार, पाली पर ओवररेटिंग की शिकायत की जांच किए जाने की पुष्टि हुई। इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जिला कृषि अधिकारी कुमारी इरम ने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद में यूरिया का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आने वाले सप्ताह में यूरिया उर्वरक की नई रैक भी लगने की संभावना है, जिससे किसानों को बिना किसी परेशानी के समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रशासन की इस सख्ती से जहां उर्वरक वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, वहीं किसानों को राहत मिलने की उम्मीद भी बढ़ी है।

नोडल अधिकारी ने करनपुर में आयोजित ग्राम चौपाल में सुनीं लोगों की समस्याएं

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

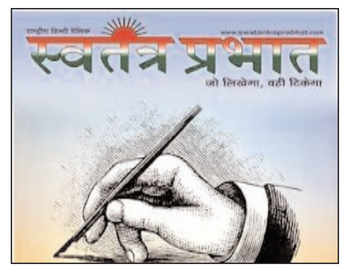

रायबरेली, नोडल अधिकारी जनपद/प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उ0प्र0 शासन सुभाष चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में वि0खण्ड बछरावां की ग्राम पंचायत करनपुर में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में नोडल अधिकारी ने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों से समस्या के समाधान के संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने अब तक की गई कार्यवाहियों की भी समीक्षा की। उन्होंने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन व दिव्यांग पेंशन की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित कराया जाये कि सभी पात्र लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिलें कोई भी पात्र लाभार्थी लाभ से वंचित न रहे। चौपाल में ग्रामीण विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, स्वच्छ पेयजल कार्यक्रम, राशन वितरण प्रणाली, पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उ0प्र0 स्पॉन्सरशिप योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन योजना-ग्रामीण, राज्य/केन्द्रीय वित्त योजना, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित आदि योजनाओं पर चर्चा की गयी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव द्वारा 03 बच्चों को अन्नप्रासन व 03 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता, सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार, उप जिलाधिकारी महराजगंज गौतम सिंह, जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार, परियोजना निदेशक, (जिला ग्राम्य विकास अभिकरण) सतीश प्रसाद मिश्रा, खण्ड विकास अधिकारी बछरावां एस0बी0सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी सौम्यशील सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी सृष्टि अवस्थी, जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा, जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी मोहन त्रिपाठी सहित सम्बन्धित अधिकारीगण व ग्राम प्रधान रहमत अली एवं क्षेत्रीय निवासी उपस्थित रहे।

सूबेदार एवं लाल साहब स्मारक फुटबॉल टूर्नामेंट: सद्भावना क्लब गोरखपुर और टाउन क्लब लालगंज सेमीफाइनल में

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। सूबेदार एवं लाल साहब स्मारक राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट के चौथे दिन दो क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में सद्भावना क्लब गोरखपुर ने सुदर्शन क्लब लालगंज को 1-0 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।मैच का शुभारंभ अतिथि राजेश सिंह फौजी, एरिया सेल्स मैनेजर अनंत शेख तथा इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। खेल के 11वें मिनट में गोरखपुर के खिलाड़ी अनंत शेख ने बाएं छोर से जोरदार शॉट मारा। गेंद गोलकीपर के हाथ से छूटकर गोल लाइन के भीतर चली गई, जिसे निर्णायक ने वैध गोल करार दिया। इसके बाद दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकीं। गोरखपुर की ओर से जितेश, तहसीम और विजय का प्रदर्शन सराहनीय रहा।दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई और टाउन क्लब लालगंज के बीच खेला गया। मैच का शुभारंभ रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक अनुज यादव ने किया। खेल के 11वें मिनट में टाउन क्लब के कृष्णा ने पहला गोल किया। तीन मिनट बाद सैफई के रोहित यादव ने बराबरी का गोल दागा। 32वें मिनट में असलम खान ने सैफई को 2-1 की बढ़त दिलाई।दूसरे हाफ में टाउन क्लब के ऋषि ने गोल कर स्कोर 2-2 कर दिया। 69वें मिनट में सैफई के अभिनव पटेल ने फिर टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन तीन मिनट बाद अर्जुन ने बराबरी कर दी। मैच समाप्ति से चार मिनट पहले कृष्णा ने शानदार निर्णायक गोल दागकर टाउन क्लब को 4-3 से रोमांचक जीत दिलाई।कार्यक्रम का संचालन बीरेंद्र शुक्ल ने किया। इस अवसर पर अध्यक्ष देवेंद्र बहादुर सिंह, राजेंद्र सिंह 'रज्जू भैया', उप सचिव अरुण कुमार सिंह 'मुन्ना', राजेंद्र सिंह राठौड़, उमेश श्रीवास्तव, पवन सिंह, भवानी श्रीवास्तव, सोमेश सिंह, अतिदेव पांडेय, रणधीर सिंह सहित बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।

इनसेट : कल खेले जाएंगे सेमीफाइनल

सेमीफाइनल मुकाबलों में डीएफए कानपुर, स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, टाउन क्लब लालगंज और सद्भावना क्लब गोरखपुर आमने-सामने होंगे।

राष्ट्रीय लोक अदालत में 181462 वादों का सुलह समझौते के आधार पर हुआ सफल निस्तारण, वादकारियों को मिला सस्ता सुलभ न्याय

स्वतंत्र प्रभात संवादाता

बरेली/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा - निर्देशन में दिनांक 13 दिसम्बर, 2025 दिन शनिवार को जनपद न्यायाधीश श्री प्रदीप कुमार सिंह-द्वितीय, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली, द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ देवी सरस्वती एवं गणेश भगवान की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों, अधिवक्ताओं एवं पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया एवं लंबित वादों का निस्तारण कराया। अपर जनपद न्यायाधीश श्री रामानन्द, नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, बरेली ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कुल 181462 वादों का सफल निस्तारण कर 300730555 रुपये की धनराशि का आदेश पारित किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में सत्र न्यायालयों द्वारा 927 वादों का निस्तारण कर 6800 रुपये की जुर्माना राशि, दीवानी न्यायालयों द्वारा 25621 वादों का निस्तारण कर 15288616 रुपये की जुर्माना राशि, फौजदारी न्यायालयों द्वारा 4664 वादों का निस्तारण कर 1939050 रुपये की जुर्माना धनराशि का आदेश पारित किया गया। लोक अदालत में गिले शिकवे दूर कर पारिवारिक न्यायालयों द्वारा 223 जोड़ो के मध्य समझौता कराया गया। प्रधान न्यायाधीश, श्री मोहम्मद अशरफ अन्सारी द्वारा 64 वादों में आपसी समझौता कराया गया, अपर प्रधान न्यायाधीश श्री संजय कुमार सिंह द्वारा 50 वादों का, श्रीमती छाया नैन द्वारा 45 वादों का व श्री ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी द्वारा 64 वादों का निस्तारण किया गया।

मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण द्वारा 216 वादों का निस्तारण कर 108114000 रुपये की समझौता धनराशि, वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा 9 वादों का निस्तारण कर 7055470 रुपये की समझौता धनराशि का आदेश पारित किया गया।

प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में 42891 वादों का, सम्भागीय परिवहन विभाग द्वारा 1563 मामलों का निस्तारण कर 816050 रुपये की समझौता राशि, पुलिस विभाग द्वारा 77159 मामलों का जिसमें 26607 ई चालानों का निस्तारण कर 26288690 रुपये की जुर्माना राशि, कैनाल न्यायालय द्वारा 7 मामलों का निस्तारण कर 700 रुपये की समझौता राशि, उपभोक्ता फोरम द्वारा 6 वादों का निस्तारण कर 3125962 रुपये की समझौता राशि, श्रम विभाग द्वारा 25 वादों का निस्तारण कर 30534434 रुपये की समझौता राशि, बी.डी.ए. द्वारा 8 वाद, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1694 मामलों का, नगर निगम द्वारा 10866 मामलों का निस्तारण किया गया तथा भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा 49 मामलों का निस्तारण कर 104783 रुपये की समझौता धनराशि एवं जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा 14043 मामलों के निस्तारण का आदेश पारित किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों एवं पुलिस अधीक्षक- यातायात, बरेली द्वारा कुल 52542 ई चालानों का निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली के अपर जनपद न्यायाधीश श्री उमा शंकर कहार ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन में जनपद न्यायालय परिसर में बैंक वादों के निस्तारण हेतु 20 पीठों का गठन किया गया जिनके समक्ष विभिन्न बैंक द्वारा बैंक ऋण से संबंधित 1511 वादों का निस्तारण किया गया एवं कुल ऋण धनराशि 107456000 रुपये वसूल की गई।

लोक अदालत में केन्द्रीय कारागार-प्रथम, बरेली में निरुद्ध बन्दियों द्वारा तैयार की गयीं हस्तशिल्प वस्तुओं एवं केन्द्रीय कारागार-द्वितीय/जिला कारागार, बरेली में निरुद्ध बन्दियों द्वारा तैयार किये गये औषधीय पौधों की प्रदर्शनी लगायी गयी एवं विक्रय किया गया। लोक अदालत परिसर में स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं का भी विक्रय किया गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री उमा शंकर कहार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आम जनता को परेशानियों से बचाने और जानकारी देने के लिए लोक अदालत परिसर में हेल्प डेस्क बनाया गया जिसमें पैरा लीगल वालंटियर उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में समस्त न्यायिक अधिकारियों, बैंक-बीमा कंपनी के अधिकारियों, अन्य न्यायिक कर्मचारियों, पराविधिक स्वयं सेवकों तथा मीडिया कर्मियों का भी योगदान रहा।

सीएचसी अधीक्षक ने फीता काटकर किया जन औषधि केंद्र का उद्घाटन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रतनपुर/महराजगंज। नौतनवां ब्लाक क्षेत्र के सीएचसी रतनपुर में शनिवार को जन औषधि केन्द्र का उद्घाटन सीएचसी अधिक्षक डॉक्टर सुरेन्द्र कुमार ने फीता काट कर किया।

जानकारी के मुताबिक नौतनवां ब्लाक क्षेत्र के रतनपुर सीएचसी में विगत कई महीनों से जन औषधि केन्द्र बंद पड़ा था। औषधि केंद्र बंद होने से आम जनमानस को महंगी दवाएं प्रयोग करना पड़ता था। जिसको देखते हुए रतनपुर सीएचसी में पुनः प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र संचालित किया गया। जन औषधि केंद्र संचालित होने से आम लोगों में खुशी का माहौल है। जन औषधि केन्द्र का शुभारंभ करते हुए सीएचसी अधीक्षक डॉ सुरेन्द्र कुमार ने कहा कि अब मरीजों को सस्ती दवाओं के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब मरीजों को सस्ती दवाएं आसानी से मिलेंगी। इस मौके पर डॉक्टर पारस नाथ, श्रीराम वर्मा,

फार्मासिस्ट निशार अहमद, अशोक कुमार, जन औषधि केन्द्र संचालक सुकदेव द्विवेदी, सीएचसी स्टाफ शिवप्रताप शुक्ल, प्रमोद कुमार, मुदिता त्रिपाठी, अजय कुमार, राकेश सहित आदि लोग मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

आर्थिक सहयोग में पुनः स्थापित कुटीर उद्योग: पूर्व ADC के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद व्यक्त

श्रीभूमि जिले के सोनबिल क्षेत्र के फाकुआ गाँव के निवासी पल्टू दास पुरकायस्थ ने अपनी मेहनत से 2019 में डालमट फैक्ट्री का निर्माण किया था। लेकिन अचानक उनकी बीमारी और परिवार की जिम्मेदारी निभाने के कारण कुटीर उद्योग बंद हो जाने से पुत्र दीपक दास पुरकायस्थ निराश हो गए। हालांकि, सेवानिवृत्त ADC और समाजसेवी निलमनी दास के सान्निध्य और आर्थिक सहयोग से डालमट फैक्ट्री को पुनः जीवित किया गया। वर्तमान संवद्धधारी दीपक दास पुरकायस्थ ने बताया कि उनके सहयोग से शुरू किए गए डालमट फैक्ट्री से पांच प्रकार की सामग्री तैयार की जा रही हैं और जिले के विभिन्न हिस्सों में बाजार में उपलब्ध कराने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं। इस प्रकार आर्थिक सहयोग के लिए आगे आए पूर्व ADC और समाजसेवी निलमनी दास के प्रति परिवार के सदस्य कृतज्ञता और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड अधिकारी कर रहा था पाकिस्तान के लिए जासूसी, असम से गिरफ्तार

नई दिल्ली। असम पुलिस ने शुक्रवार रात एक सेवानिवृत्त भारतीय वायुसेना (IAF) अधिकारी को पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से निगरानी में था और शुरुआती जांच के बाद उसे हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहलान कुलेंद्र शर्मा के रूप में हुई है, जो असम के सोनितपुर जिल के तेजपुर स्थित पटिया इलाके का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लगातार निगरानी और प्रारंभिक जांच के बाद उसे हिरासत में लिया गया।

पुलिस ने क्या दावा किया?

पुलिस का दावा है कि कुलेंद्र शर्मा कथित तौर पर पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी से जुड़े लोगों के संपर्क में था और उन्हें संवेदनशील जानकारियां दे रहा था। उसके मोबाइल फोन और लैपटॉप से कुछ संदिग्ध सामग्री बरामद की गई है। पुलिस को आशंका है कुछ डेटा डिलीट भी किया गया है। कुलेंद्र शर्मा भारतीय वायुसेना में जूनियर वारंट ऑफिसर के पद पर तैनात था। वह तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन में पोस्टेड था, जहां सुखोई-30 लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन मौजूद है। वह वर्ष 2002 में सेवानिवृत्त हुआ था। सेवानिवृत्ति के बाद कुलेंद्र ने कुछ समय के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी में भी काम किया था।

BNS की कई धाराओं में मामला दर्ज

सोनितपुर के डिप्टी एसपी हरिचरण भूमिज ने कहा कि आरोपी के पाकिस्तान से जुड़े होने का शक मजबूत है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही इसकी पुष्टि की जा सकेगी। पुलिस ने कुलेंद्र शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल, पुलिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मिले डेटा की जांच कर रही है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल की जा रही है।

नोएडा में चिली पोटैटो खाने से महिला और बच्ची बीमार, फूड प्वाइजनिंग की आशंका

दनकौर। कोतवाली क्षेत्र के जुनेदपुर गांव निवासी एक महिला और उसकी दो वर्षीय बेटी चिली पोटेटो खाने से फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गईं। दोनों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता का स्वजन का कहना है कि वह इसकी शिकायत खाद्य विभाग के अधिकारियों और पुलिस से करेंगे। पीड़ित सपना के पति सुमित ने बताया कि छह दिसंबर को वह कनारसी गांव के पास स्थित एक पिज्जा की दुकान से चिली पोटेटो लेकर आए थे, जिन्हें खाने के कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी सपना और दो वर्षीय बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई। दोनों को उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। स्वजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। सुमित का आरोप है कि चिली पोटेटो बनाने में खराब और बासी सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, जिस कारण यह फूड प्वाइजनिंग की घटना हुई है। उन्होंने बताया कि जब वह इस संबंध में शिकायत करने दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार ने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय उनके साथ अभद्रता की और मारपीट पर उतारू हो गया। अस्पताल में कई दिनों तक इलाज चलने के बाद शनिवार को महिला और बच्ची की हालत में कुछ सुधार हुआ है। सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने बताया कि अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है, शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी। विभाग की ओर से लगातार जांच अभियान चला कार्रवाई की जा रही है।

खाकी बनाम खादी :-55 दिनों बाद टूटा सियासी सस्पेंस, भाजपा नेता प्रीतम सिंह किसान लखनऊ से गिरफ्तार

● कई सवाल अब भी कायम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

डॉ. दीक्षा शर्मा, पुलिस अधीक्षक | प्रीतम सिंह किसान, पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष

हमीरपुर :- खाकी और खादी के बीच चल रहा 55 दिनों का रहस्यमय खेल आखिरकार शुक्रवार को खत्म हो गया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान, जो बीते 55 दिनों से लापता बताए जा रहे थे, उन्हें पुलिस ने लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। जिस नेता की तलाश में हमीरपुर से लखनऊ तक पुलिस की टीमें भटकती रहीं, वही नेता सूबे की राजधानी में एक मकान में छिपकर रह रहा था। इस खुलासे के साथ ही पुलिस की कार्यशैली और पूरे मामले की सच्चाई पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

पेट्रोल पंप से शुरू हुआ खेल

मामले की शुरुआत 18 अक्टूबर को राठ स्थित प्रीतम सिंह के पेट्रोल पंप पर हुए विवाद से हुई थी। विवाद के बाद पुलिस उन्हें थाने ले गई, लेकिन इसके बाद वे अचानक 'लापता' हो गए। पुलिस की ओर से पहले तो अनभिज्ञता जताई गई, फिर धीरे-धीरे मामला रहस्यमय होता चला गया। आखिर इतने बड़े राजनीतिक चेहरे का यूं गायब हो जाना, वह भी पुलिस कार्रवाई के बाद, आम लोगों की समझ से परे था।

लापता या भूमिगत?

प्रीतम सिंह के लापता होने की कहानी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। 31 अक्टूबर को पुलिस ने उनके पेट्रोल पंप पर ताले तोड़कर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन वहां भी कुछ हाथ नहीं लगा। इसी बीच यह चर्चा तेज होती गई कि प्रीतम सिंह वास्तव में लापता नहीं थे, बल्कि जानबूझकर भूमिगत होकर पूरे घटनाक्रम को दिशा दे रहे थे।

हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंचा मामला

28 नवंबर को प्रीतम सिंह के भाई वीर सिंह ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर दी। कोर्ट के आदेश ने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी। सवाल यह था कि यदि नेता पुलिस की हिरासत में नहीं थे, तो फिर इतने दिनों तक उनका कोई पता क्यों नहीं चल सका? कोर्ट के दबाव के बाद ही पुलिस ने तलाश तेज की और अंततः लखनऊ में उनकी मौजूदगी का खुलासा हुआ।

55वें दिन गिरफ्तारी, सवाल बरकरार

शुक्रवार को पुलिस ने लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र स्थित एक मकान से प्रीतम सिंह

किसान को हिरासत में लिया। इसके साथ ही 55 दिनों से चला आ रहा सियासी और प्रशासनिक सस्पेंस खत्म हुआ, लेकिन कई सवाल अब भी हवा में हैं। क्या यह केवल पुलिस की लापरवाही थी या किसी स्तर पर मिलीभगत? इतने दिनों तक राजधानी में छिपे रहना कैसे संभव हुआ? अब प्रीतम सिंह को हमीरपुर न्यायालय लाया गया है और पुलिस तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की बात कह रही है। लेकिन यह मामला अब सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि खाकी और खादी के रिश्तों पर उठे सवालों की कहानी बन चुका है।

गाली-गलौज व मारपीट के मामले में चार महिलाओं पर मुकदमा दर्ज

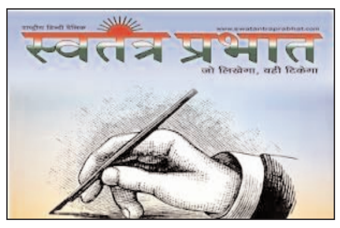

हमीरपुर :- कुरारा थाना क्षेत्र के इन्दपुरी गांव में गाली-गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चार महिलाओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इन्दपुरी गांव निवासी आरती पत्नी सूरज प्रसाद ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि वह अपने घर के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान पड़ोस की रामश्री ने अकारण गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर रामश्री ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर रामश्री की परिजन उर्मिला, ज्योति और ममता भी मौके पर पहुंच गई और एक राय होकर पीड़िता के साथ मारपीट करने लगीं। पीड़िता के अनुसार, मारपीट में उसे गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रामश्री, उर्मिला, ज्योति और ममता के खिलाफ मारपीट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

चलती बोलेरो में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ,अफरा-तफरी के बीच निकाली गईं सवारियां

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर :- बेतवा नदी के पुल पर शनिवार तड़के उस समय हड़कंप मच गया, जब चलती बोलेरो कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील होने लगी। बोलेरो में सवार दो लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए कार को पुल के बीचों-बीच खड़ा किया और जान बचाने के लिए बाहर कूद पड़े। कुछ ही पलों में आग इतनी भड़क गई कि पूरी बोलेरो धू-धूकर जलने लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बोलेरो पूरी तरह जल चुकी थी। आग बुझाने के बाद जली हुई कार को हाइड्रा मशीन की मदद से पुल से बाहर खींचा गया, ताकि यातायात बहाल किया जा सके।

पुल पर लगा लंबा जाम

बोलेरो में आग लगने के कारण बेतवा पुल पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कुछ देर के लिए हाईवे पर आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला।

तड़के हुआ हादसा, बड़ा खतरा टला

सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पवन

पटेल ने बताया कि तड़के बोलेरो कार में दो लोग सवार होकर कुछेछा की ओर जा रहे थे। जैसे ही वाहन बेतवा नदी के पुल पर पहुंचा, अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और इंजन से आग उठने लगी। आग लगते ही दोनों कार सवारों ने बिना देर किए वाहन रोक दिया और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।

कार सवार सुरक्षित

कार में सवार लोगों की पहचान शहर निवासी हरिओम शर्मा और झांसी निवासी उनके साथी पुष्पेंद्र शर्मा के रूप में हुई है। दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें कोई शारीरिक चोट नहीं आई है।

बड़ा हादसा टला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि कार सवार कुछ सेकेंड की भी देरी करते, तो बड़ा हादसा हो सकता था। समय रहते कार से बाहर निकलने के कारण जान-माल का नुकसान टल गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

बाइक चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा, पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर :- राठ कस्बा में बाइक चोरी की कोशिश करते एक युवक को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने उसकी पिटाई कर दी और बाद में कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। घटना रामलीला मैदान के पास बिजली विभाग के कार्यालय के निकट की है। जानकारी के अनुसार, बिजली विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी की मोटरसाइकिल बिजली बिल कार्यालय के पास खड़ी थी। इसी दौरान शराब के नशे में धुत एक युवक चोरी की नीयत से मोटरसाइकिल को पैदल ही खींचकर ले जाने लगा। युवक की हरकत पर आसपास मौजूद लोगों की नजर पड़ गई। रामलीला मैदान क्षेत्र निवासी बबलू ने बताया कि जैसे ही लोगों को बाइक खींचे जाने की जानकारी मिली, उन्होंने युवक का पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर राठ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया युवक उरई का निवासी है, जो राठ कस्बे के चरखारी रोड इलाके में अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

नेतृत्व क्षमता प्रदान करने के लिए सुगमकर्ताओं को मिला प्रशिक्षण

चित्रकूट: स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी के अन्तर्गत पावर एंजिल सशक्तिकरण एवं नेतृत्व क्षमता प्रदान करने के लिए सुगमकर्ताओं की दो दिवसीय ब्लाक स्तरीय कार्यशाला बीआरसी में आयोजित की गई। जिसमें खण्ड शिक्षा अधिकारी अतुल दत्त तिवारी ने प्रमाण पत्र वितरित कर सभी सुगमकर्ताओं से प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को विद्यालय में क्रियान्वयन का आवाहन किया। प्रशिक्षण में संदर्भदाता गिरीश कुमार मिश्र व कविता मिश्रा ने बताया कि राज्य परियोजना समग्र शिक्षा लखनऊ के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय स्थित बीआरसी में कुल 132 सुगमकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। 10 दिसम्बर से शुरु यह प्रशिक्षण तीन बैचों में 16 दिसम्बर तक चलेगा। प्रशिक्षण के माध्यम से मीना मंच के गठन, उद्देश्य, पावर एंजिल के चयन, पास्को एक्ट, बालिका सुरक्षा, परख माड्यूल, अरमान माड्यूल, वीरांगना पोर्टल तथा आधा फुल कॉमिक के माध्यम से तकनीकि का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों के समग्र कौशलों के विकास पर विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

चुनूबाद शिक्षा निकेतन में धूम-धाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव

● संस्थान द्वारा गरीबों को बांटे गए कम्बल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर ब्यूरो :- मुस्करा विकासखण्ड के निवादा गांव स्तिथ चुनूबाद शिक्षा निकेतन में शनिवार के दिन संस्थान का 18वां वार्षिकोत्सव बड़ी ही धूम-धाम से मनाया गया।विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किये। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रहे दद्दू प्रसाद ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर व पुष्पांजलि देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।सुबह साढ़े दस बजे शुरू हुए कार्यक्रम में बच्चों ने नाटिकाएं एवं रिकॉर्डिंग पर भाव नृत्य आदि प्रस्तुत किये।वहीं संस्थान के प्रबंधक शिवप्रसाद कुशवाहा एवं उनकी पत्नी गुड्डो कुशवाहा (पूर्व प्रधान)ने गरीबों को कम्बल भी बांटे।विद्यालय प्रबंधक ने बताया कि कुल 8 सौ गरीबों को कम्बल वितरण किया गया। मुख्य अतिथि दद्दू प्रसाद ने अपने संबोधन में लोगों से कहा कि मनुष्य जीवन मे तीन सबसे बड़े दान होते हैं ,जीवन दान ,रक्त दान और शिक्षा दान हैं ,लेकिन इनमें सबसे बड़ा दान शिक्षा दान होता है।इसके बाद राजनीतिक समीकरण साधते हुए दलित और पिछड़ों की एक जुटता का राग अलापने लगे।कार्यक्रम के समापन पर सभी बच्चों को प्रोत्साहन पुरुष्कार दिए गए और

,प्रबंधक शिवप्रसाद कुशवाहा ने सभी आगन्तुकों के प्रति आभार व्यक्त किया।इस दौरान क्षेत्र के तमाम सम्भ्रान्त लोग मौजूद रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत में 18,626 वादों का निस्तारण, 11.48 करोड़ रुपये का हुआ समझौता

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर :- जनपद न्यायालय परिसर में शनिवार को जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर मनोज कुमार राय द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोक अदालतों का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को सरल, सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है, जिससे अधिक से अधिक लोग न्याय व्यवस्था से लाभान्वित हो सकें। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जनपद के विभिन्न न्यायालयों में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर कुल 18,626 वादों का निस्तारण किया गया। न्यायालयों, राजस्व विभाग एवं बैंकों के माध्यम से कुल 11 करोड़ 48 लाख 90 हजार 123 रुपये की धनराशि समझौते के रूप में प्राप्त हुई। न्यायालयों द्वारा निस्तारित वादों में लगभग 3.53 करोड़ रुपये, जबकि राजस्व विभाग एवं बैंकों के मामलों में लगभग 7.95 करोड़ रुपये की धनराशि का निस्तारण किया गया। बैंकों के कुल 22,621 मामलों में से 674 प्रकरणों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हुआ। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित अनेक न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं न्यायालय कर्मी उपस्थित रहे। लोक अदालत के दौरान उ0प्र0 ग्रामीण बैंक के सहयोग से दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु जनपद न्यायालय में एक व्हीलचेयर समर्पित की गई, जो गेट नंबर-1 पर उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही न्यायालय परिसर में चिकित्सा विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया,

जिसमें लगभग 200 लोगों का परीक्षण कर दवाएं वितरित की गईं। कार्यक्रम में जिला कारागार द्वारा निर्मित पर्यावरण अनुकूल कपड़े के थैलों, आरसेटी द्वारा तैयार उत्पादों तथा गैर सरकारी संगठनों के जागरूकता स्टॉल भी लगाए गए, जिन्हें लोगों ने सराहा।

जमीनी विवाद में स्टांप विक्रेता पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर :- राठ कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते एक स्टांप विक्रेता पर लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना उस समय हुई जब पीड़ित राठ तहसील से काम निपटाकर घर लौट रहा था। बहर गांव के पास रास्ते में घात लगाए बैठे दो हमलावरों ने उसे रोककर बेरहमी से पीट दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने किसी तरह घायल को बचाया और राठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां डॉ. माजिद ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत नाजुक देखते हुए उसे हमीरपुर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। सीएचसी में इलाज के दौरान घायल स्टांप विक्रेता परमलाल पुत्र उदयभान, निवासी बहर गांव, ने बताया कि गांव में खेत को लेकर उनका लंबे समय से विवाद चल रहा है। उन्होंने हदबंदी का मुकदमा दायर किया था, जिसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पत्थरगड्डी भी कराई गई थी। इसके बावजूद विपक्षी उनके

खेत पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। परमलाल का आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में कोतवाली, एसडीएम और तहसीलदार को कई बार शिकायतें दीं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी लापरवाही के चलते आरोपियों के हौसले बढ़े और उन्होंने उन पर हमला कर दिया। मारपीट में उनके शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने राठ कोतवाली में लिखित तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी ने बताया कि घायल का मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, एक दर्जन गाड़ियां आपस में टकराइ

दादरी। घने कोहरे के कारण ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दो अलग-अलग जगहों पर सड़क हादसे हुए। जिसमें चक्रसेनपुर फ्लाईओवर पर तीन गाड़ियां और समाधिपुर फ्लाईओवर पर करीब एक दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी क्षतिग्रस्त गाड़ियों को सड़क से हटाकर सुरक्षित जगह पर खड़ा कर दिया। हादसों में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। यातायात सामान्य रूप से चल रहा है। आगे की जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

दर्जनों गाड़ियां आपस में टकराई

इस हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त होने के साथ ही कई लोग घायल हो गए। कई वाहनों के आपस में टकराने के कारण रास्ते में लंबा जाम लग गया। क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस ने टोल के माध्यम से हटवाकर जाम खुलवाने का काम किया जिसमें लंबा वक्त लग गया। हादसे की स्थान पर एक सफेद कार डिवाइडर पर चढ़ी हुई देखी जा सकती है, जिसका बोनट बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसी कार के बगल में ट्रक और ट्रक के नीचे फंसी एक कार भी देखी जा सकती है। यह हादसा घने कोहरे के चलते रास्ता साफ न दिखने से हुआ है।

ठेकेदार ने लाइसेंसी राइफल से खुद को मारी गोली

● पत्नी बोली कुछ दिनों से थे परेशान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर :- बेलाताल निवासी हाल मुकाम मुस्करा के एक ठेकेदार ने अपनी लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली।गोली मारने की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया गंभीर हालत में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया,गंभीर हालात होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। उसकी पत्नी ने बताया कि कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान थे। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच करने में जुटी। मुस्करा कस्बा के राठ रोड पर बेलाताल निवासी अशोक राजपूत अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। अशोक ने कांति नाम की महिला से प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद परिवार वालों ने अशोक से संबंध तोड़ लिए थे। जिसके बाद वह मुस्करा कस्बे में अपना घर बनाकर रहने लगा था। अशोक की पत्नी कांति सरकारी कंपोजिट स्कूल में टीचर हैं। जबकि अशोक ठेकेदारी का काम करता है शुक्रवार रात अशोक ने अचानक अपनी लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली उसके जबड़े को भेदती हुई निकल गई। गोली की आवाज सुनकर कमरे में पहुंची कांति ने अशोक को गंभीर हालत में देखकर मुस्करा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां से डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालात होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पत्नी कांति ने बताया कि उनके पति पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थे। पूछने पर किसी से कुछ नहीं बताया करते थे। इसी तनाव के कारण अशोक ने खुद को गोली मारने का कदम उठाया। दंपती का एक 5 वर्षीय बेटा भी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम पर होगा बंगाल के लोक भवन के एक द्वार का नाम, राज्यपाल ने लिया निर्णय

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कोलकाता। बंगाल के राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने उपलक्ष्य में एक साल तक चलने वाले जश्न कार्यक्रमों की घोषणा की है।

इसी के साथ राज्यपाल ने लोक भवन (पूर्व में राजभवन) के दक्षिण-पश्चिम द्वार का नाम बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। लोक भवन के एक अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल रविवार को लोक भवन में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम में दक्षिण-पश्चिम द्वार का नाम औपचारिक रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम पर रखेंगे।

लोक भवन ने बयान किया जारी

लोक भवन द्वारा जारी एक बयान में बताया गया कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक साल तक चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत 10 नवंबर को राज्यपाल के नेतृत्व में वंदे मातरम् मार्च के साथ ही शुरू हो गया था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों, शिक्षकों और बंगाली समाज के हर तबके के लोग शामिल हुए थे। राज्यपाल ने वंदे मातरम के दूरगामी असर और रेलिवेंस पर काम करने, रिसर्च करने, पब्लिकेशन निकालने और वर्कशाप और सेमिनार करने के लिए लोक भवन में एक बंदे मातरम चेयर भी शुरू की है। इसके अलावा लोक भवन ने बांग्ला भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए वंदे मातरम पुरस्कार भी शुरू किए हैं। रविवार को राज्यपाल वंदे मातरम की लौ को बनाऐ रखने के लिए लोक भवन में नित्यशिखा जलायेंगे। बयान में बताया गया कि समारोह की शुरुआत हुगली जिले के चुंचुड़ा में एक कार्यक्रम से होगी, जहां बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम गीत लिखा था।

150 जगहों पर आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम

बंडेल, चिनसुरा, हुगली से एक रंगारंग जुलूस निकाला जाएगा। वंदे मातरम थीम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम बंगाल के अलग-अलग हिस्सों में 150 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में राज्यपाल स्वयं या लोक भवन के अधिकारी शामिल होंगे।